



हिलव्यू समाचार

सभी सुधि पाठकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएँ

जयपुर
रविवार, 28 अगस्त
2022

R.N.I. No. RAJHIN/2014/56746



hillviewsamachar@gmail.com



सो रहा प्रशासन!

रवि जैन, आयुक्त जेडीए

गोपालपुरा बाईपास

हजारों विद्यार्थियों की जान खतरे में!

सो रही सरकार!



सूडीएच मंत्री शांति धारीवाल

अवैध भवनों में चलते कोचिंग संस्थानों को भवन खाली करने का नोटिस क्यों नहीं थमा रहा अब तक जेडीए?

शालिनी श्रीवास्तव
हिलव्यू समाचार के लगातार चेताने पर भी जेडीए की आर्ख, नाक, कान बन्द क्यों है यह समझना मुश्किल नहीं है क्योंकि बिल्डिंग व व्यापारियों से अच्छे संबंध आड़े आ जाते हैं लेकिन क्या इनका खामियाजा मासूम विद्यार्थी भुगतेंगे?

गोपालपुरा बाईपास की किसी भी बिल्डिंग में आप जाकर निरीक्षण करें तो आप पाएंगे कि उसकी बिल्डिंग में बिल्डिंग बायलॉज का भरपूर उल्लंघन हुआ है और इन्हीं अवैध भवनों में सैकड़ों कोचिंग संस्थान चल रहे हैं भवन मालिक को डेरों रुपये से मतलब

है जो किराए के रूप में उसे मिल रहा है और कोचिंग वालों को भी डेरों एडमिशन से मतलब है जो धन की वर्षा उन पर फ्रीस के रूप में बरसा रहे हैं दोनों की अवैधता लाखों विद्यार्थियों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है क्योंकि...

- इन बिल्डिंग्स में ज्यादातर प्रवेश व निकास का एक ही द्वार है। किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के लिए कोई इंतजाम नहीं।
- आगजनी होने पर एक दूसरे से सटी सभी बिल्डिंग्स में पढ़ रहे विद्यार्थियों की जान खतरे में आ सकती है।

- फायर एनओसी तो दूर की बात है क्योंकि बिल्डिंग अवैध है तो मिल नहीं सकती लेकिन फायर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हैं।
- सेटबैक का अपना मसला है लेकिन यहाँ पार्किंग के लिए सड़क पर कब्जा आम बात है।
- लाखों की फीस वसूलते ये संस्थान अवैध भवनों

में किसकी शैय पर चलायमान हैं क्या विधायक, क्या मंत्री, क्या जेडीए, क्या नगर निगम? कौन है इन सबका जिम्मेदार? या जब कोई दुर्घटना होती आगजनी या सड़क हादसा होगा आपस में सब जिम्मेदार को ढूँढने निकलेंगे और एक-दूसरे पर दोषरोपण करके पल्ला झाड़ेंगे।



गोपालपुरा बाईपास@ सुबह 10 बजे



गोपालपुरा बाईपास@ शाम 4 बजे और यही स्थिति शाम 6 बजे भी



गोपालपुरा बाईपास@ सुबह 11 बजे से 12 बजे तक



गोपालपुरा बाईपास@ दोपहर 02 बजे

गोपालपुरा बाईपास का प्राइम टाइम दृश्य

सुबह 9.00 बजे से 10.00 बजे तक, 10.30 से 11.30 तक, 12.00 बजे दोपहर से 2.30 बजे तक, शाम 4.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक, शाम 6.30 से शाम 8.00 बजे तक जब आसानी से बच्चों की जान पर मंडराए खतरे को खुली आँखों से देखा जा सकता है। पहचान नहीं बताने, नाम व फोटो नहीं छापने की शर्त पर हिलव्यू समाचार की टीम को स्थानीय पीडित रहवासियों व राह से गुजरने वाले लोगों ने बताया कि...

- इस प्राइम टाइम के दौरान हजारों बच्चे कोचिंग में आते और कोचिंग से छूटते हैं। मुख्य मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। तेज दौड़ते वाहनों में अपनी जान पर खेलते बच्चे सड़क पार करते आसानी से देखे जा सकते हैं।
- शराब की दुकानों का इस शैक्षणिक माहौल में चलना बेहद निन्दनीय है।
- बड़े लड़कों को लड़ते-झगड़ते, मंडलियों में घूमते और माहौल बिगाड़ते हुए आसानी से देर शाम व रात को देखा जा सकता है।
- इन कोचिंग संस्थानों की वजह से आसपास के आवासीय भवनों में डेरों होस्टल और पीजी पनप गए हैं जो कि आसपास के अन्य लोगों का सरदर्द बन गए हैं।
- सामान्य जनजीवन बेहद प्रभावित हो रहा है लेकिन कहने-सुनने वाला कोई नहीं।
- प्रभावशाली लोगों से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत आम आदमी नहीं कर सकता इसीलिए सिर्फ सहना आदत बन चुकी है या ज़्यादा से ज़्यादा मकान बेचकर कहीं और जाना ही समाधान निकाल लिया है।

आखिर क्यों?

सबसे बड़ी बात कि गोपालपुरा बाईपास पर एक साथ चल रहे हैं शिक्षण संस्थान व शराब के प्रतिष्ठान? क्या देश की भावी पीढ़ी यानी विद्यार्थियों को यह वातावरण देना शर्मिंदगी का विषय नहीं सरकार के लिए? आखिर क्यों?

कोचिंग संस्थानों के आसपास शराब की दुकानें, जाम होता ट्रैफिक और बढ़ रही आपराधिक गतिविधियाँ क्या जेडीए को नजर नहीं आ रही बिल्डिंग्स व कोचिंग बायलॉज के हिमाव से सबको नोटिस की बजाय कमर्शियल पट्टे बाँटने की तैयारी किस आपसी समझ और मिलीभगत के तहत कर रहा है जेडीए।

कहाँ हैं बिल्डिंग्स व कोचिंग संस्थान के बायलॉज



- सुप्रीम कोर्ट 2016 के आदेशानुसार कमर्शियल या इन्स्ट्रुक्शनल एरिया होना ज़रूरी है।
- फायर के फुज़ा इंतजाम ज़रूरी है।
- पार्किंग की व्यवस्था सुव्यवस्थित होना आवश्यक है।
- कमर्शियल भवन आने-जाने के अलग-अलग द्वार होना अनिवार्य है।
- बिल्डिंग बायलॉज अनुसार हर बिल्डिंग का सेटबैक छोड़कर निर्माण होना ज़रूरी है।
- स्ट्रूट की सीट सीमा निर्धारित होना आवश्यक है।

स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल क्यों इन कोचिंग संस्थानों को जेडीए से नोटिस जारी नहीं करवा रहे, गोपालपुरा बायपास से प्रतापनगर कोचिंग हब में शिफ्ट होने का। ये अवैध कोचिंग सेंटर यहाँ से हटेंगे तो राजस्व हाउसिंग बोर्ड द्वारा डबलप किये जाने वाला कोचिंग हब ई-ऑक्शन में 500-700 करोड़ रुपए में बिक सकता है। इससे राजकोष को भारी फ़ायदा हो सकेगा। इस दौरान लॉटरी से 55 करोड़ का राजस्व मिल सकता है किंतु ई-ऑक्शन से दोगुने-तिगुने दाम मिल सकते हैं।

प्लॉट नंबर 497, गोपालपुरा बायपास पर खड़ी होटल ग्रैंड सफ़ारी पर क्या बिल्डिंग बायलॉज के नियम लागू नहीं होते?



सर्जन्स एन्क्लेव, B-293,10 बी स्कीम, गोपालपुरा बायपास पर किस अधिकार से इस भवन के मालिकों ने मुख्य सड़क को खुद की निजी पार्किंग के लिए रिजर्व कर लिया है और रिजर्व के 3-4 बोर्ड सड़क पर लगा दिए हैं। जेडीए प्रवर्तन शाखा कहीं सो रही है?



प्लॉट नंबर 420, गोपालपुरा बायपास पर सीना ताने खड़ी होटल सफ़ारी & रेस्टोरेन्ट क्या बिल्डिंग बायलॉज के दायरे से बाहर है?



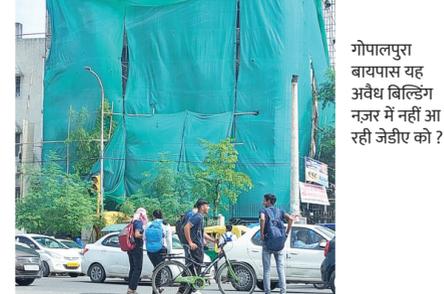
प्लॉट नंबर 5-58 का ये लंबी-चौड़ी अवैध बिल्डिंग जेडीए की निगाहों में क्यों नहीं जो आधी सड़क को पार्किंग के नाम पर घेरे रहती है और बिल्डिंग बायलॉज से कोसों दूर है?



ग्रैंड सफ़ारी के पास प्लॉट नंबर 595, गोपालपुरा बायपास क्या यह जेडीए की प्रवर्तन शाखा की नजरों से ओझल हो गया है?

गोपालपुरा बाईपास हो या टॉक रोड यहाँ चलते बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करोड़ों अरबों के व्यापारी वर्ग हैं। सपने खरीदते ये कोचिंग संस्थान देश की सेवार्थ नहीं बल्कि अपने अर्थ यानी पैसे के लिए काम करते हैं। जेडीए या नगर निगम जिसके भी अधिकार में जो एरिया आता है वो इन कोचिंग संस्थानों पर उदारता बरसाने के बजाए आदेश नोटिस जारी करे कि यह इंस्टीट्यूट्स केवल और केवल कमर्शियल बिल्डिंग्स व कमर्शियल एरिया में ही चलाए जा सकते हैं और वह कॉमर्शियल एरिया शहर के मुख्य मार्गों व बेहद व्यस्त आवागमन के एरिया में नहीं होना चाहिए अन्यथा बन्द करवा दिए जाएंगे। तब कहीं जाकर शहर को व्यवस्थित किये जाने की ओर एक क़दम बढ़ाया जा सकता है। गोपालपुरा बायपास

को आदर्श बनाने के लिए अवैध निर्माणकर्ताओं को पालने पोसने की कोई आवश्यकता नहीं न ही एक वक्त बाद उन पर किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत उदारता बरसाने की आवश्यकता है।



गोपालपुरा बायपास यह अवैध बिल्डिंग नज़र में नहीं आ रही जेडीए को?

गोपालपुरा बायपास मुख्यमार्ग को आदर्श बनाने व कोचिंग संस्थान मुक्त करवाने की इस मुहिम में अपनी सकारात्मक सहमति देने के लिए अपना वोट मैसेज द्वारा या व्हाट्सएप द्वारा 9460079061 पर अवश्य भेजें। आपकी पहचान व नंबर गुप्त रखे जाएंगे।
adarshgopalpurabypass.Yes
असहमति दर्ज करने पर यस के स्थान पर NO टाइप करें।

विपक्षी एकता की न पकने वाली खिचड़ी

सम्पादकीय

बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने के साथ ही विपक्षी एकता के अभियान को फिर से धार देने के प्रयास हो रहे हैं। जद-यू नेता तो नीतीश कुमार को पीएम पद का पात्र बनाने में लगे ही हुए हैं, राजद नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी उनकी पैरवी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव यही चाहेंगे कि नीतीश कुमार जितनी जल्दी संभव हो, पीएम पद की दौड़ में शामिल हों और मुख्यमंत्री को कुर्सी पर उन्हे बैठाने का अवसर मिले।

यह अवसर उन्हे मिलना भी चाहिए, क्योंकि राजद बिहार का सबसे बड़ा दल है। जद-यू नेता नीतीश कुमार को पीएम पद के लिए गुणवान बनाने के साथ यह भी कहने में लगे हुए हैं कि वह भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम करेंगे। कटिनाई यह है कि जद-यू और राजद के अलावा अन्य कोई प्रमुख दल न तो इस पर उत्साह दिखा रहा है और न ही यह कहा रहा है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को चुनौती देने में सबसे समर्थ नेता होंगे। नीतीश बिहार के बड़े नेता अवश्य हैं, लेकिन अब उनकी छवि सुशासन बाबू की नहीं रही। जब तक जद-यू का राजद में विलय नहीं हो जाता, तब तक यकीन के साथ यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह फिर से पालाबदल नहीं करेंगे।

बिना वैकल्पिक एजेंडे के कैसे जीतेंगे देश का भरोसा



एक वक्त था जब गुजरात माडल के जवाब में बिहार माडल का बखाना होता था, लेकिन अब तो खुद नीतीश कुमार भी अपने गवर्नेस माडल के बारे में बात नहीं करते। क्यों नहीं करते, यह वही जानें, लेकिन यह सबको और विशेष रूप से राज्य की जनता को भी पता है कि बिहार विकास के पैमानों पर अन्य राज्यों से पीछे है। जद-यू और राजद के नेता कुछ भी कहें, बिहार के महागठबंधन में शामिल कांग्रेस भी नीतीश को पीएम पद लायक कहने से बच रही है। कांग्रेस से ऐसी आशा भी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यदि नीतीश पीएम पद के प्रत्याशी बनेंगे तो फिर राहुल गांधी क्या करेंगे? गांधी परिवार से जबसे केंद्र की सत्ता छिनी है, तबसे वह यह माने बैठा है कि इस देश पर शासन करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि किसी मजबूरी और विशेष रूप से नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की चाह में कांग्रेस नीतीश के पीछे खड़ी हो जाती है, तो भी इसकी गारंटी नहीं कि ममता बनर्जी, के. चंद्रशेखर

बनाम केजरीवाल होगा। भारत की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह याद रहे कि फिलहाल आम आदमी पार्टी का एक भी सदस्य लोकसभा में नहीं है। वह भगवंत सिंह मान के इस्तीफे से खाली हुईं संसद लोकसभा सीट भी नहीं बचा सकी।

2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी चाहे जितनी सीटें जीत ले, इसके आसार न के बराबर हैं कि अन्य विपक्षी दल केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे आएंगे। विपक्षी एकता के ऐसे धूमिल परिदृश्य के बाद भी यह तय है कि विपक्ष को एकजुट करने की बातें भी होती रहेंगी और पहल भी। वास्तव में इस तरह की पहल सदैव होती रहती है। बहुत दिन नहीं हुए जब ममता बनर्जी विपक्षी दलों को एकजुट करने के अभियान पर निकली थीं, लेकिन अब वह न केवल निष्क्रिय हैं, बल्कि उन्होंने पहले राष्ट्रपति चुनाव और फिर उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता को कमजोर करने का काम किया। राष्ट्रपति के चंद्रशेखर राव ने विपक्ष को एक करने का अभियान शुरू किया, लेकिन वह नाकाम रहा और अब वह भी करीब-करीब निष्क्रिय हैं। एक समय विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश शरद पवार ने भी की थी, लेकिन बात नहीं बनी। रही-सही कसर महाविकास आघाड़ी सरकार के पतन ने पूरी कर दी। विपक्षी दलों को एकजुट करने की नाकाम कोशिश प्रशांत किशोर भी कर चुके हैं। अब वह अपनी जन सुराज यात्रा में व्यस्त हैं।

राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन विपक्षी एकता न पकने वाली खिचड़ी इसलिए है, क्योंकि आज न तो कोई जयप्रकाश नारायण हैं, न हरिकृष्ण सिंह सुरजीत और न ही वीपी सिंह। अब जो भी विपक्षी नेता विपक्ष को एकजुट करना चाह रहा है, वह प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं। यह सपना देखने का अधिकार हर नेता को है, लेकिन जो दल मोदी सरकार को हटाने के लिए सक्रिय हैं, वे यह नहीं बता पा रहे कि वह इस सरकार को हटाने और केंद्र की सत्ता पाने के बाद करेंगे क्या?

इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसी तमाम समस्याएँ हैं, लेकिन कोई विपक्षी दल यह बताने की स्थिति में नहीं कि वह इन समस्याओं से कैसे पार पाएगा? वादे करना अलग बात है और उन्हे पूरा करना अलग बात। इसे इससे समझा जा सकता है कि दस लाख सरकारी नौकरियाँ देने के अपने चुनावी वादे पर तेजस्वी यादव अग्र-मण्य कर रहे हैं। स्पष्ट है कि बिना वैकल्पिक एजेंडे, देश का भरोसा जीतने वाले समर्थ चेहरे और ठोस विमर्श के विपक्षी एकता संभव नहीं।



कैसा हो मेकअप जब आंखों पर लगा हो चश्मा

तो काला चश्मा लगाने के लिए लड़कियाँ हर पल बेकरार रहती हैं लेकिन जब आंखों पर नजर का चश्मा लगा जाता है तो वह दुखी हो जाती हैं, क्योंकि तब उन्हें लगता है, अब उनके मेकअप करने या न करने का क्या फायदा, चेहरे की सारी खूबसूरती तो चश्मे ने ही खराब कर दी है।

वेहरा डरावना सा दिखता है. मतलब यह कि अगर ये पता है कि रोज चश्मा पहनना है तो यह बात भी जान ले कि ऐसा क्या उपाय करें जिससे नाक के दोनों तरफ चश्मे के गड्ढे न बनें. लेकिन अगर नोज पैड के दोनों तरफ निशान पड़ ही गए हैं तो मेकअप करते समय इन्हे ब्लूटी बाम, बीबी क्रीम या फाउंडेशन से हर हाल में छिपा लें, वरना सारे मेकअप की ऐसी की तैसी हो जाएगी.

आइसोरो की ग्रोथ पर ध्यान रखें. निश्चित समय पर आइसोरो को सेट कराएं, इससे आंखों में सजीव चमक दिखेगी, वरना खाली-खाली दिखेगा.

FASHION

जोन

बना रहेगा स्टाइल स्टेटमेंट

आपका सारा स्टाइल स्टेटमेंट बिगड़ जाता है. बरखात में क्या पहनकर ऑफिस जाएं, ये एक चुनौती बन जाती है. इन सुझावों को अपनाकर आप अपना स्टाइल स्टेटमेंट बनाए रख सकती हैं. इस सीजन में कलॉर पैट और कलॉर बॉटम इन हैं. इसके अलावा सॉफ्ट कलर के शर्ट और ब्लाउज, कैजुअल और फॉर्मल जैकेट जो आप अपने ड्रेस के साथ पहन सकें, अपने वार्डरोब में शामिल करें.

आंखों में नजर का चश्मा लगा जाए तो कभी नस बात को लेकर दुखी नहीं होना चाहिए कि इससे आप कम खूबसूरत लगेंगी. याद रखिए, मनोविद कहते हैं कि चश्मे वाली लड़कियाँ गैर चश्मे वाली लड़कियों के मुकाबले 10 फीसदी ज्यादा अट्रैशन पाती हैं. हां, यह भी सच है कि कई बार खूबसूरत आंखें चश्मे के पीछे छुपी जाती हैं. लेकिन अगर सज्ज होकर कालात्मक ढंग से मेकअप किया जाए तो आंखें नहीं छुपींगी, बल्कि ज्यादा खूबसूरत दिखेंगी.

इस बात को भी समझिए कि यदि आपकी आंखों में नजर का चश्मा चढ़ चुका है तो यह आसानी से उतरने वाला नहीं है. इसके साथ ही आपको जीना सीखना होगा. तो क्यों न इसके साथ बेहतर दिखना भी सीख लें. इसमें भी आपकी मदद मेकअप ही करेगा.

ऐसा हो आईलाइनर

अगर आपकी आंखों में नजदीक की नजर का चश्मा लगा है तो लोअर लाइन पर ह्राइट या बेज कलर का लाइनर लगाएं. इससे आंखें बड़ी लगती हैं. वैसे चश्मा लगाने वाली लड़कियों के लिए आईलाइनर का एक सीधा सा फार्मुला होता है. आपके चश्मे का फ्रेम जितना मोटा हो, आईलाइनर भी उतना ही मोटा होना चाहिए. चाहे तो ब्रिंस लाइनर भी लगा सकती हैं. रंग कोई भी हो सकता है, काला, बरगंडी या ब्राउन, अगर सही से लगाया जाए तो इन सभी कलर से आंखें खिल उठती हैं.

नोज पैड के निशान का ध्यान रखें

जब हम कई वर्षों तक लगातार चश्मा पहनते हैं तो नाक के आगे की ओर दोनों तरफ गहरे निशान पड़ जाते हैं, इसे नोज पैड कहते हैं. कई बार तो यह निशान इतने तीखे होते हैं कि आंख से चश्मा हटाने ही नंगा

औषधीय गुणों से भरपूर दालचीनी

DIET मैजिक

हमारी रसोई में पाई जाने वाली दालचीनी प्राकृतिक गुणों से भरपूर होती है, जिसके कारण इसका उपयोग रसोई के गरम मसालों के साथ-साथ औषधि के रूप में किया जाता है. यह रसोई में पाया जाने वाला एक ऐसा मसाला है जिसका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है. दालचीनी में प्राकृतिक रूप से शर्करा की मात्रा पाई जाती है जो मधुमेह लोगों के लिए काफी फायदेमंद होती है. गरम मसालों और औषधि के रूप में इस्तेमाल होने वाली दालचीनी रक्तचाप को स्थिर रखने में फायदेमंद है. साथ ही में ये रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के साथ कोलेस्ट्रॉल की समस्या, हृदय रोग, उच्च

रक्तचाप, कैंसर, पीसीओ, अल्सर, योनि खमीर संक्रमण, जैसी बीमारियों को दूर करने में काफी मदद करता है. इसके साथ ही शरीर में होने वाले घाव को शीघ्र ही खरब कर उसे पूरी तरह से भर देता है.

कुछ प्रिंटेड ड्रेस और जैकेट अपने वार्डरोब में रखें. इसे आप जब चाहें, बाहर जाने के दौरान पहन सकती हैं.

बारिश में ऐसे शूज का चुनाव करें जो आपके पैरों को बरसात में जमा होने वाले पानी से सुरक्षित रख सकें. अगर आप लेदर के शूज पहन रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि वह पानी में भीगे नहीं.

इस मौसम में शॉर्ट को ज्यादा तरजीह दें. यह बरसात में कंपर्टबल भी है. हमेशा सिंथेटिक ब्लेंड्स फेब्रिक के शॉर्ट ही चुनें. यह गीले होने पर जल्द ही सूख जाते हैं. लाइट फेब्रिक के शॉर्ट का चुनाव न करें.

अगर आप रैनकोट पहनने से बोर हो गए हैं तो ट्रेंच कोट ट्राई करें. यह इमर्जिंग ट्रेंड फिज्ने कई वर्षों से भारत में जोर पकड़ रहा है. यह कई तरह के डिजाइन और कलर में उपलब्ध है. यह न सिर्फ आपके स्टाइल को खूबसूरत बनाता है, बल्कि आपको मौसम की मार से भी प्रोटेक्ट करता है.

अपने मानसून आउटफिट को क्लीन लुक देने के लिए परफेक्ट एक्सेसरीज का चुनाव करें. बैग के लिए ब्राइट कलर के प्लारिस्टिक टोटे और स्लिंग बैग आपके लिए बेहतर हैं.

बरसात में शूज या गम बूट्स आपको गंदे पानी से बचाते हैं. कलरफुल ट्रैडी विलेज फॉलोअप, लोफर्स, जैली शूज या कमीज आपके लुक को सुपर कूल बनाएंगे.

किस्ती भी महिला के लिए गर्भ धारण करना एक सुखद पल होता है.

HEALTH जोन

उसे कई सावधानियाँ भी बरतनी पड़ती हैं, खासकर कहीं घूमने जाते समय. अक्सर यात्रा को लेकर गर्भवती महिलाएँ दुविधा में रहती हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतकर आप पेंगनेसी में भी ट्रेवल कर सकती हैं.

पेंगनेसी में शुरुआती 3 महीने और लास्ट के 3 महीने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं. इस दौरान साफ करने से बचना चाहिए. शुरुआती महीने में मिसकैरिज का खतरा बहुत ज्यादा होता है. पहले तीन महीने के बाद वॉमेन्टिंग की प्रॉब्लम भी कम हो जाती है.

मलाई से ज्यादा मात्रा में घी निकालने के लिए उसमें बर्फ डालकर मिक्सी में चलाएं, इससे सारा मक्खन अलग होकर ऊपर आ जाएगा और मट्टा नीचे रह जाएगा. इस मट्टे या छाछ का इस्तेमाल आप रवा इडली का बेंटर बनाने के लिए कर सकते हैं.

इंस्टैंट क्रिस्पी पोटेटो चिप्स बनाने के लिए आलू के पतले स्लाइस काटकर इन्हें बर्फ वाले पानी में थोड़ी देर के लिए रख दें और उसके बाद फ्राय करें.

लौकी का कोपता या हलवा बनाने के लिए इसे कट्टकस करने के बाद जो पानी निकले, उससे आटा गूँथ लें. इससे परांठे न सिर्फ सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे बल्कि बेहतर भी होंगे.

प्रेगनेसी में जब करनी हो ट्रेवलिंग

ट्रेवलिंग गर्भवती महिला को डाइट तथा व्यायाम के रूटीन को प्रभावित करती है. एक गर्भवती महिला को ट्रेवलिंग के दौरान स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन, सही प्रकार से आराम व खूब सारे फ्लूइड्स तथा लाइट एक्ससाइज भी जरूरी होती है.

वैसे तो प्रेगनेसी के दौरान हवाई यात्रा सुरक्षित नहीं होती लेकिन किन्हीं कारणों से यदि आपको हवाई यात्रा करनी पड़े तो आपको गर्भवस्था के 14 - 28 सप्ताहों के बीच में ही यात्रा करनी चाहिए, लेकिन उसके पहले अपने डाक्टर की सलाह लेना कभी न भूलें.

गर्भवती महिलाओं में सफर के दौरान जो मिवलाना और उल्टी आना आम शिकायत है. दरअसल, गर्भवस्था के दौरान शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन बढ़ जाते हैं जो जी मिवलाने के लक्षणों से लड़ने की शरीर की क्षमता को कम कर देते हैं.

ट्रेवलिंग उन महिलाओं के लिए नुकसानदेह हो सकती है, जिनकी प्रेगनेसी हाई रिस्क पर हो.

मलाई से ज्यादा मात्रा में घी निकालने के लिए उसमें बर्फ डालकर मिक्सी में चलाएं, इससे सारा मक्खन अलग होकर ऊपर आ जाएगा और मट्टा नीचे रह जाएगा. इस मट्टे या छाछ का इस्तेमाल आप रवा इडली का बेंटर बनाने के लिए कर सकते हैं.

इंस्टैंट क्रिस्पी पोटेटो चिप्स बनाने के लिए आलू के पतले स्लाइस काटकर इन्हें बर्फ वाले पानी में थोड़ी देर के लिए रख दें और उसके बाद फ्राय करें.

लौकी का कोपता या हलवा बनाने के लिए इसे कट्टकस करने के बाद जो पानी निकले, उससे आटा गूँथ लें. इससे परांठे न सिर्फ सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे बल्कि बेहतर भी होंगे.

गार्लिक ब्रेड

सामग्री- मक्खन, लहसुन की कलियाँ (बारीक कटी हुई), घिनी पलेवस, इटैलियन सीजनिंग या ऑरिगेनो, ब्रेड स्लाइस, चीज स्लाइस, स्वीट डॉन् (इच्छानुसार), नमक स्वादानुसार.

विधि- एक कटोरी में मक्खन लें और उसे घिघला लें. अब पिघले हुए मक्खन में बारीक कटा लहसुन डालकर अच्छे से चलाएं और थोड़ी देर के लिए अलग रख दें. इस तैयार किए गए गार्लिक बटर में घिनी पलेवस और ऑरिगेनो डालें. उसके बाद गार्लिक बटर को ब्रेड स्लाइस पर अच्छे से लगाएं और ऊपर से स्वीट डॉन् डालें. अब उसके ऊपर चीज स्लाइस रखें और तब पर सेकने के लिए रख दें. (ध्यान रहे कि इसे करारा बनाने के लिए आप इसे धीमी आंच पर ही सेंकें.)

साबूदाना डोसा

सामग्री- 1 कप साबूदाना, 2 बड़े चम्मच दही, 1/2 कप सवां के चावल (भार), नमक आवश्यकतानुसार.

विधि- साबूदाना को 4 घंटे के लिए और चावल को लगभग 30 मिनट के लिए भिगो दें. एक ब्लेंडर में भीगे हुए साबूदाना, भार, दही और थोड़ा पानी डालें. गाढ़ा पेस्ट बनाने के लिए ब्लेंड करें. स्वादानुसार नमक डालें और अच्छी तरह फेंटें. मध्यम आंच पर एक तवा गरम करें. अब एक नॉन स्टिक तवे पर तेल की कुछ बूंदें डालें और 2 टेबल स्पून पानी डालें. कढ़ाई से हल्के हाथों से पोंछ लें. तब पर 2 चम्मच घोल डालें और पतली परत बनाने के लिए गोलाकार गति में फैलाएं. दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने पर साबूदाना डोसा परोसने के लिए तैयार है.

खीरा-चना बोट चाट

सामग्री- खीरा, प्याज, टमाटर, अनार, उबले आलू, उबले चने, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, नींबू का रस, सफेद नमक, काला नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हरी चटनी, सेब.

विधि- खीरा को अच्छे से धोएं और फिर लंबाई में बीच से काटें. एक चम्मच की मदद से खीरे के बीच को निकाल लें और एक तरफ रखें. उबले आलू, प्याज, टमाटर को बारीक काट लें. इसी के साथ अनार के दाने निकालकर अलग रखें. अब एक बर्तन में चना लें, फिर इसमें बारीक कटे प्याज, टमाटर, उबले आलू डालें. बारीक कटा हरा धनिया व हरी मिर्च भी डालें और फिर अच्छे से मिस करें. इसमें हरी चटनी, सफेद नमक, काला नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर मिस करें. अनार के दाने डालें और अब इस चाट को कट्टे हुए खीरे में डालें और अच्छे से स्प्रेड करें. फिर इस पर सेब व

एक नज़र

जिला कलक्टर ने किया दशहरा मैदान का निरीक्षण



असलम रोमी

कोटा। जिला कलक्टर ओपी बुनकर ने शनिवार को सीएडी स्थित दशहरा मैदान का निरीक्षण कर आगामी राष्ट्रीय मेला दशहरा के सफल आयोजन को लेकर निगम के अधिकारियों को दिशा-निर्देश प्रदान किये। इस अवसर पर आयुक्त नगर निगम दक्षिण राजपाल सिंह, उप सचिव गजेन्द्र सिंह, उप सचिव अम्बालाल मीणा सहित निगम के विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जिला कलक्टर ने कहा कि कोटा का दशहरा मेले के शुभारंभ से लेकर समापन तक विभिन्न कार्यक्रमों आयोजित किये जाते रहे हैं इन सभी आयोजनों में निगम के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी समन्वित प्रयास कर टीम भावन के रूप में कार्य कर मेले को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिये। मेले

में दुकान आवंटन से लेकर, विद्युत सजा, साफ-सफाई, पार्किंग, कार्यक्रमों में आयोजन को लेकर दी जाने वाली सभी जिम्मेदारियों को समय रहते पूरा कराने के निर्देश दिये। मेले के आयोजन के दौरान साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाये। निगम की ओर से सभी दुकानदारों को अपनी अपनी दुकान के लिए डस्बिन उपलब्ध कराये जाने साथ ही निगम की ओर से साफ-सफाई और अनावश्यक कचरा नहीं फैलाने के अपील एवं पोस्टर का वितरण भी कराएँ जिससे मेला परिसर साफ-सफाई बनी रहे। जिला कलक्टर ने दशहरा मैदान में पड़े हुए पुराने वाहन जो अनुपयोगी हो गये हैं उनका कमेटी बनाकर निलाम करने के निर्देश दिये जिससे निगम को राजस्व का प्राप्ति हो सके। विजयश्री रंगमंच एवं रामलौला मंच का भी अवलोकन किया।



3 शांतिर दुपहिया वाहन चोर गिरफ्तार, 9 बाइक बरामद

हिलव्यू समाचार

नागौर। थाना पादुकला पुलिस ने दुपहिया वाहन चोरों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई कर तीन शांतिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की कुल 9 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों ने पादु कला, रियांबड़ी, मेड़ता और डेगाना से यह वाहन चोरी करना स्वीकार किया है।

नागौर एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि 21 अगस्त को थाना बिलाड़ा जोधपुर निवासी इकबाल खान ने एक रिपोर्ट थाना पादु कला में दी। जिसमें बताया कि वह आज सुबह करीब 10:00 बजे पादु कला में इंद्रगणी होटल के पास अपनी रिश्तेदारी में आया था। घर के बाहर बाइक खड़ी कर अंदर गया, जब बाहर आया तो वहां बाइक नहीं थी।

रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया। मामले के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी जोशी द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा व सीओ नंदलाल सैनी एवं थानाधिकारी सुमन चौधरी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर गांव डोडियाना से आरोपी चैनाराम उर्फ चैन बावरी (22) निवासी पूसाजी की ढाणी पादु खुद, कानाराम बावरी पुत्र रमजी राम (23) निवासी बोटन थाना गोटन तथा सुरेश बावरी पुत्र श्वण राम (23) निवासी मंडल जोधा थाना पादु कला को दस्तगार कर चोरी की उक्त बाइक समेत नौ बाइक बरामद की है।

राज्य सरकार द्वारा महिला समानता दिवस के उपलक्ष्य में पाँच दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन हुआ

नीलम मुंजाव

जयपुर। महिलाओं को आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्तर पर समानता का दर्जा दिलाने और उनके प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से महिला समानता दिवस मनाया जाता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समानता प्राप्त करने के लिए महिलाओं ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और यह संघर्ष अभी भी जारी है। महिलाओं की समानता को प्रतिपादित करने के लिए हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस मनाया जाता है। महिला समानता की शुरुआत 1893 में न्यूजीलैंड ने की इसके बाद 1920 में अमेरिका ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया।

इस वर्ष महिला समानता दिवस की थीम महिलाओं के वोट के अधिकार का जश्न मनाया है इस सोच के साथ राज्य सरकार की ओर से इस बार एक विस्तृत कार्यक्रम मनाया गया। समानता दिवस के उपलक्ष्य में पाँच दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई इन कार्यक्रमों में प्रदेशनी लगाई गई और महिलाओं की सफलता के विषय पर परिचर्चाओं का आयोजन किया गया जिसमें महिला सशक्तिकरण पर



महिला समानता दिवस की शुभकामनाएं

विस्तृत विचार किया गया इस क्रम में मुख्य कार्यक्रम गत शुक्रवार जयपुर में आयोजित हुआ कार्यक्रम में प्रदेश भर से विभिन्न स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर

पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला निधि का लोकार्पण किया इस निधि से महिलाएं अपनी रोजमर्रा के कार्यों और व्यवसाय के लिए लड़ प्राप्त कर सकेंगे और महिलाओं को संबोधित

महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने के लिए कानून के साथ-साथ सामाजिक सोच में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महिला विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही

हैं जिसमें वे आत्मनिर्भर बन सकें। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है जिससे महिलाएं सशक्त हुई हैं और उनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के स्वास्थ्य शिक्षा और आर्थिक विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं को भी रेखांकित किया।

कार्यक्रम को महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूषेण, मुख्य सचिव उषा शर्मा और मजदूर किसान शक्ति संगठन के फाउंडर अरुणा राय ने भी संबोधित किया। स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एमओयू पर करार किया गया जिससे महिला समूह अपने द्वारा निर्मित उत्पाद को ऑनलाइन बिक्री कर सकेंगी। इससे पूर्व के दिनों में जवाहर कला केंद्र में स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई इसके अलावा कई परिचर्चाएं भी आयोजित की गईं जिनमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर विचार विमर्श किया गया महिला समानता दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम सरकार का महिलाओं के विकास के प्रति सोच का की पहल है।

छात्रसंघ चुनाव कोटा: 11 में निर्दलीयों का कब्जा, 3 में एबीवीपी व 2 में एनएसयूआई ने मारी बाजी, जेडीबी आर्ट्स में एबीवीपी, पूरा पैलल जीता

कोटा। कोटा शहर में हुए छात्रसंघ चुनाव में कोटा यूनिवर्सिटी समेत जिले के 11 सरकारी कॉलेजों में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय ने कब्जा जमाया। जबकि 3 कॉलेजों में एबीवीपी व 2 कॉलेज में एनएसयूआई को फतह मिली। इनमें एक शहर व एक ग्रामीण कॉलेज से एनएसयूआई, शहर में तीन कॉलेज में एबीवीपी व बाकी सभी में निर्दलीय ने कब्जा जमाया।

कोटा यूनिवर्सिटी में निर्दलीय का कब्जा: कोटा यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय अजय ने जीत हासिल की है। उन्होंने एबीवीपी की अंतिम को हराया। अजय को 281 मत मिले है। अंतिम को 215 मत मिले। अजय 66 मतों से विजय रहे। कॉमर्स कॉलेज में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय अर्पित ने जीत हासिल की है।

जेडीबी आर्ट्स में एबीवीपी का पूरा पैलल जीता: जेडीबी आर्ट्स में एबीवीपी का पूरा पैलल जीता है। यहां एबीवीपी की शिवानी दुबे व निर्दलीय निशा के बीच टक्कर थी। शिवानी दुबे ने 136 वोट से जीत हासिल की। शिवानी को 569 वोट मिले। निर्दलीय निशा को 433 वोट मिले। उपाध्यक्ष पद पर अंजलि, महासचिव रिंकी विजयी रही। संयुक्त सचिव प्रियंका मीणा को निर्दलीय निर्वाचित किया। बात दें कि 23 अगस्त की सुबह निर्दलीयों के नामांकन खारिज होने पर एबीवीपी पैलल ने जीत का जश्न मनाया था, लेकिन कुछ



घंटे बाद ही अंतिम वैध नामांकन सूची में निर्दलीयों के नाम जोड़ने से एबीवीपी ने विरोध जताया था। कॉलेज गेट पर धरने पर बैठ गई थी। जेडीबी साइंस कॉलेज में एनएसयूआई का कब्जा: जेडीबी साइंस कॉलेज में एनएसयूआई ने कब्जा जमाया है। यहां एनएसयूआई की अंजली ने

निर्दलीय नीलु को मात दी है। यहां कुल 491 वोट पड़े थे। अंजली को 443 वोट मिले। जबकि निर्दलीय नीलु को 35 वोट मिले। 13 वोट खारिज हुए। एनएसयूआई की महिमा उपाध्यक्ष, मुस्कान, महासचिव सलिन का संयुक्त सचिव पद पर पहले की निर्दलीय निर्वाचित हो चुकी थी।

जेडीबी कॉमर्स में एबीवीपी विजयी: जेडीबी कॉमर्स में अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी से दीप्ति ने निर्दलीय माधवी को हराया। दीप्ति को 129 वोट मिले। निर्दलीय माधवी को 81 मत मिले। एनएसयूआई से चेतना को 65 वोट मिले। यहां उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की मानसी, महासचिव स्वाती चुनाव जीती है। संयुक्त सचिव पद पर ज्योति कुमारी निर्दलीय रही।

राजकीय साइंस कॉलेज में निर्दलीय व आर्ट्स में एबीवीपी राजकीय साइंस कॉलेज में निर्दलीय आशीष अध्यक्ष बने। उन्हें 661 मत मिले। जबकि ललित को 322 मत मिले। आशीष 339 मतों से विजयी रहे। उपाध्यक्ष स्वदेश सिंह, महासचिव नितेश व संयुक्त सचिव आवेश विजयी रहे। राजकीय कला महाविद्यालय में एबीवीपी से मनीष सामरिया अध्यक्ष बने।

साढ़े तीन बीघा भूमि पर दो नवीन अवैध कॉलोनीयों को जेडीए ने किया ध्वस्त



हिलव्यू समाचार

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जून-13 में निजी खतेदारी करीब 3.5 बीघा कृषि भूमि पर 02 नवीन अवैध कॉलोनीयों का पूर्णतः ध्वस्त किया गया। साथ ही जेडीएस्वामित्व के सरकारी गैर मुमकीन आम रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जून-05 में सुओमोटो के तहत: 02 आवासीय कॉलोनी की रोड़ सीमाओं को अतिक्रमण मुक्त करवाया। रोड़ सीमा के करीब 21 अतिक्रमण-चबूतरे, लोहे की जालियां, दीवारों से निर्मित एनक्लोजर इत्यादि को हटवाया जाकर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्री रघुवीर सैनी ने बताया कि जून-13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित कस्बा-चौमू के जविप्रा स्वामित्व के सरकारी गैर मुमकीन आम रास्ते खसरा नं. 4137 पर स्थानीय कास्तकारों द्वारा आम रास्ते के दोनों तरफ करीब 5-5 फीट चौड़ाई व 500 मीटर लम्बाई पुनः अवैध कब्जा-अतिक्रमण कर तारबंदी, मिट्टी की डोल, बाउण्ड्रीवाल, लेट-बॉथ इत्यादि बनाकर कब्जा-अतिक्रमण कर सरकारी आम रास्ते को पूर्ण अवरुद्ध कर रखा था। जिससे सड़क निर्माण कार्य नहीं हो पाने से स्थानीय आमजन को रास्ते को लेकर भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। जिसकी शिकायत प्राप्त होते ही अखिलम्व जून से रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाकर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर जून-13 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डी.बी. सिविल रीट पिटीशन नं. 7688/2019 सुओमोटो के तहत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा आज दिनांक 25.08.2022 के क्षेत्राधिकार महेश नगर क्षेत्र में अवस्थित 'पाशवनाथ' कॉलोनी में मकानों के आगे रोड़ सीमा में करीब 15 स्थानों पर अतिक्रमण कर बनाये गये 05 चबूतरे व 10 स्थानों पर लॉन हेतु लगाये गये लोहे के रंगल, जालियां/दीवारों से निर्मित एनक्लोजर, इत्यादि अवैध निर्माण-अतिक्रमणों को जून-05 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डी.बी. सिविल रीट पिटीशन नं. 7688/2019 सुओमोटो के तहत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा आज दिनांक 25.08.2022 जून-13 के क्षेत्राधिकार अवस्थित कस्बा-चौमू में ही हाईवे से लगते हुये राजमहल गार्डन, न्यू देगोर स्कूल के पास, भोजलाई कट में खसरा नं. 748/3, 748/2, 750/2, 745/3 व 742/3 में करीब 02 बीघा निजी खतेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये 'गिरांज विहार' के नाम से नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिनाजेडीएकी अनुमति व स्वीकृति के विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनायी जा

रही मिट्टी की सड़क व अन्य अवैध निर्माण की सूचना प्राप्त होते ही आज अखिलम्व जून-13 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को विफल किया गया। धारा 175 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु उपायुक्त जून-13 को पत्र लिख जावेगा तथा जविप्रा का ध्वस्तीकरण में हुये व्यय-खर्च की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जावेगी। जेडीएस्वामित्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डी.बी. सिविल रीट पिटीशन नं. 7688/2019 सुओमोटो के तहत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा आज दिनांक 25.08.2022 के क्षेत्राधिकार महेश नगर क्षेत्र में अवस्थित 'पाशवनाथ' कॉलोनी में मकानों के आगे रोड़ सीमा में करीब 15 स्थानों पर अतिक्रमण कर बनाये गये 05 चबूतरे व 10 स्थानों पर लॉन हेतु लगाये गये लोहे के रंगल, जालियां/दीवारों से निर्मित एनक्लोजर, इत्यादि अवैध निर्माण-अतिक्रमणों को जून-05 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डी.बी. सिविल रीट पिटीशन नं. 7688/2019 सुओमोटो के तहत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा आज दिनांक 25.08.2022 जून-13 के क्षेत्राधिकार अवस्थित कस्बा-चौमू में ही हाईवे से लगते हुये राजमहल गार्डन, न्यू देगोर स्कूल के पास, भोजलाई कट में खसरा नं. 748/3, 748/2, 750/2, 745/3 व 742/3 में करीब 02 बीघा निजी खतेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये 'गिरांज विहार' के नाम से नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिनाजेडीएकी अनुमति व स्वीकृति के विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनायी जा

पिंकसिटी प्रेस क्लब

खरी-खरी पुस्तक का विमोचन समारोह हुआ संपन्न



जयपुर। पत्रकार लेखक राजनीतिक चिंतक अशोक भटनागर राष्ट्रव्यज द्वारा लिखित पुस्तक खरी खरी का विमोचन आज पिंक सिटी प्रेस क्लब के श्री प्रकाश मीडिया सेंटर में विमोचन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि मुमताज मसीह, अध्यक्षता-फारुख अफरीदी वरिष्ठ व्यंग्यकार, लेखक एवं ओएसडी (मुख्यमंत्री) सहित विशिष्ट अतिथियों में एल सी भारतीय, सदस्य प्रेस कार्डसिल एवं इंडिया, अरुण जोशी, अतिरिक्त निदेशक सूचना जनसंपर्क निदेशालय तथा अरुण शर्मा, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सहित सभी वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार

एवं प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों ने शिरकत की। अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि मुमताज मसीह ने कहा कि मैंने बरसों से पत्रकार साथियों से बहुत कुछ सीखा है। भटनागर से मेरे 40 साल पुराने संबंध है यह बोलते भी खरी खरी हैं तथा लिखते भी खरी खरी हैं। अध्यक्षीय भाषण में फारुख अफरीदी ने कहा कि आज पत्रकारों को पत्रकारिता के साथ-साथ देश की वर्तमान परिस्थितियों पर लिखित रूप में पुस्तकें प्रकाशित करनी चाहिए जो एक शताब्दियों के लिए दस्तावेज की तरह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बने। अतिरिक्त निदेशक डीआईपीआर



अरुण जोशी ने कहा कि पिंक सिटी प्रेस क्लब में साहित्यिक गतिविधियों को निरंतर किया जाना आवश्यक हो गया है। पिंक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुकेश मीणा ने उपस्थित सभी पत्रकार साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम

प्रेस क्लब में साप्ताहिक साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन करेंगे। एल सी भारतीय ने कहा कि वह हमेशा पत्रकारों की समस्या का निस्तारण करने के लिए भारत सरकार के स्तर पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक सत्य पारीक

ने उपस्थित श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पुस्तकों की समीक्षा प्रकाशित की जानी चाहिए। चाहे वह आलोचनात्मक ही क्यों ना हो इससे लेखकों का मनोबल बढ़ता है। मंच संचालन वरिष्ठ पत्रकार एवं पिंक सिटी प्रेस क्लब के पूर्व

अध्यक्ष एल एन शर्मा ने किया तथा उन्होंने कहा कि आज पत्रकारिता में खरी-खरी कहने वाले तथा खरी-खरी लिखने वालों का नितांत अभाव हो गया है। भटनागर की पुस्तक ने सभी युवा पत्रकारों को एक नई दिशा दिखाने का काम किया है। लेखक भटनागर ने पुस्तक के बारे में बताया कि पुस्तक में वर्तमान देश के हालात और राजनीति में आई गिरावट पर कई व्यंग्य और आलेख इस पुस्तक में संकलित किए गए हैं। सभी पाठकों से अनुरोध करते हुए कहा कि वे पुस्तक के बारे में लेखक को अपनी-अपनी समीक्षा से अवगत कराएं जिससे आगामी पुस्तकों में अगर कोई त्रुटि रही हो तो उसे सुधारा जा सके। समारोह के अंत में सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए और खरी-खरी के संपादक सहयोगी विमल सिंह तंवर और राजकुमार मल्लोत्रा को सम्मानित किया गया।

विनम श्रद्धांजलि

पत्रकार सलीमुरहमान
खिलजी पत्रकारिता क्षेत्र में
चमत्कारी व्यक्तित्व रहे



एक जांबाज, एक कलमकार, एक पत्रकार सलीमुरहमान खिलजी यूँ अचानक हमें अलविदा कह जायेंगे यह हमने ख्यालों-ख्यालों में भी नहीं सोचा था। अल्लाह उनकी माफ़िफत करे, जन्नतुल फ़िरदौस में उन्हें आला मुक़ाम अता फरमाये। वे एक कलमकार, पत्रकार, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक, प्रबन्धक, विज्ञापन एडवाइजर रहे वे बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। पत्रकारों की सियासत में अगवा रहे सलीमुरहमान खिलजी ने खुद अपने बल पर जांबाज पत्रिका को सांध्य अंक के अलावा मॉर्निंग एडिशन के रूप में भी खुद की ऑफसेट

मशीन पर प्रकाशन शुरू किया। पत्रकारिता के स्कूल में सलीमुरहमान खिलजी का एक ही नारा रहा 'जुल्म ज़्यादाती के खिलाफ संघर्ष हमारा है' सलीमुरहमान खिलजी लघु समाचार पत्रों की तरफ से पत्रकारिता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कई प्रशिष्ठ पत्रकारों के उस्ताद भी रहे पत्रकारिता में खबरों को कैसे हासिल करें? कैसे लिखें? कैसे संपादित करें? अखबार प्रकाशन का प्रबंधन कैसा हो? विज्ञापन नीति कैसी हो? वार्षिक ब्योरा कैसे भेजा जाए? अखबार वितरण व्यवस्था बेहतर कैसे की जाए? वे सभी को सिखाते थे। वर्तमान में कोरोना संकट काल से कई बड़े अखबारों के जब पेज कम हो गए। प्रकाशक का प्रकाशन के प्रति नजरिया बदला लेकिन सलीमुरहमान ने और उनकी कलम, उनकी पत्रकारिता, उनके जांबाज अखबार के वही रंग बिरंगे, नियमित, तीखे तेवर रहे।

अख़्तर खान अकेला
कोटा राजस्थान

कागजों तक ही सीमित रही शहर के नालों की सफाई

हिलव्यू समाचार

कोटा। पूर्व पार्षद ब्रजेश शर्मा नौटू, हेमा सक्सेना, मधु कुमावत, धामू मेहरा, इंद्रकुमार जैन, चंद्रप्रकाश सोनी ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि शहर के हर बाजार व हर गली में पानी भरने से शहरवासियों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि शहर की हर गली व मुख्य बाजार में भरे पानी ने दोनों नगर निगमों के वर्षा पूर्व नालों की सफाई पर किए गए करोड़ों रुपयों के खर्च की पोल खोल कर रख दी है। पूर्व पार्षद ने आरोप लगाया कि दो नगर निगम बनाने के पीछे यह तर्क दिया गया था कि नगर निगम द्वारा किए जाने वाले कार्यों

की सही तरीके से मोनिटरिंग हो सकेगी वह तो हुआ नहीं बल्कि निगम पर जहां आर्थिक बोझ बढ़ गया वहीं भ्रष्टाचार भी चरम पर पहुंच गया। अब निगम के काम सिर्फ कागजी खानापूर्ति तक ही सिमट कर रह गए हैं। सभी ने कहा कि बरसात से पहले महापौर ने नालों के पास खड़े होकर बड़े-बड़े फोटो जारी करवाए जिसकी हकीकत चंद घंटों की बारिश में ही जनता के सामने आ गई। पूर्व पार्षदों ने आरोप लगाते हुए कहा कि नालों की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपयों की बंदरबांट हुई है। नालों की सफाई सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई थी जिसकी हकीकत शहर के सामने है।

फसल खराब होने की सूचना वर्षा के दौरान 72 घंटों में देना अनिवार्य

हिलव्यू समाचार

कोटा। जिले में वर्षा का दौर लगातार जारी रहने के कारण खरीफ फसलें प्रभावित हुई हैं। जिन किसानों द्वारा खरीफ फसल के तहत फसल बीमा करा रखा है। उन्हें 72 घंटे के अन्दर ऑनलाइन फसल खराबे की सूचना जिले की संसूचित बीमा कम्पनी को देने का आह्वान किया गया था। उप निदेशक कृषि विस्तार खेमराज शर्मा ने बताया कि किसान ऑनलाइन फसल खराबे की सूचना जिले की संसूचित बीमा कम्पनी बजाज एलार्ज

जनरल इश्योरेंस कम्पनी लि. के टोल फ्री नम्बर 18002095959 पर व कम्पनी के फार्मिन्नर ऐप के माध्यम से दर्ज कर चुके हैं। यदि किसानों द्वारा कराते समय वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो सात दिवस में पूर्ण सूचना निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित बीमा कम्पनी को आवश्यक किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना के अनुसार फसल खराबे की सूचना निर्धारित अवधि तक नहीं देने पर बीमा क्लेम नहीं मिल पायेगा।

मुख्यमंत्री गहलोत ने हवाई सर्वे कर जाने बाढ़ से हुए नुकसान के हालात और ईआरसीपी पर की चर्चा

असलम रोमी (हिलव्यू समाचार)

कोटा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिले में अतिवर्षा से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का गत गुरुवार को जनप्रतिनिधियों के साथ हवाई सर्वे किया तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोन्टेसरी नयापुरा में बनाए गए आश्रय स्थल पहुंचकर प्रभावितों से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक सूझ-बूझ से जल भराव से प्रभावित क्षेत्रों में कोई जनहानि नहीं हुई। उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों से रूबरू होकर जल भराव से उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली तथा आश्रय स्थल पर की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया एवं प्रभावित परिवारों को विश्वास दिलाया कि उनके घरों में हुए नुकसान का सर्वे कराकर आपदा निवारण निगमों के अनुसार त्वरित रूप से सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ के बारे में भी विस्तार से जानकारी



दी। जिसमें नेहरू कॉलोनी निवासी मुताज, गुड्डो, फरीदा, फरजाना तथा खाई रोड़ निवासी कौशलया सेनी, पार्षद नीलोफर मन्टू ने मुख्यमंत्री को सरकार की

विभिन्न योजनाओं से मिल रहे लाभ के बारे में बताया। प्रभावित परिवारों ने खाद्यान्न योजना, मुख्यमंत्री चिरजीवी योजना से लाभान्वित होने के बारे में जानकारी दी।

ईआरसीपी में काम आए व्यर्थ जा रहा पानी-मुख्यमंत्री: मुख्यमंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हाड़ती से चम्बल, कालीसिंध, परवन नदियों का

पानी व्यर्थ बहकर सागर में मिलता है। इसका सदुपयोग पूर्वी राजस्थान केनाल परियोजना में किया जाए तो निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों भी जल का लाभ ले सकेंगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए लगातार मांग की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा 9 हजार करोड़ का प्रावधान किया है, नौनरा बांध बन चुका है, ऐसे में केन्द्र सरकार को भी आगे आकर इस परियोजना के लिए सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में बड़े बांध बन गए हैं, उनकी सहायता के बाद ही इस परियोजना को शुरू किया गया। 13 जिलों में पेयजल के लिए वर्तमान में इस परियोजना का क्रियान्वयन आवश्यक है। ईआरसीपी में व्यर्थ बहकर जा रहे पानी से भी कम मात्रा में काम लिया जायेगा इससे हमेशा इस क्षेत्र में बाढ़ से होने वाले नुकसान को भी रोका जा सकेगा तथा 13 जिलों की प्यास भी बुझेगी।

छबड़ा-छीपाबड़ौद विधायक सिंघवी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा

हिलव्यू समाचार

छबड़ा बारां। छबड़ा-छीपाबड़ौद विधायक व पूर्व मंत्री प्रतापसिंह सिंघवी ने छीपाबड़ौद तहसील में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षेत्र लक्ष्मीपुरा, हरनावदाशाहजी, दीगोदजांगीर, पीपल खेडी, हल्लेसरा, नारेडा, कालाटोल, कलमोदिया, पथरी, ब्रहमाखेडी, लम्बावर, सारथल, टाकोडा, अमलावदा खरण, सुखनेरी मालोनी, बडाई, भावपुरा एवं बोरादा में हुए नुकसान का जायजा लिया। ग्राम हरनावदा शाहजी में भाजपा कार्यकर्ता गुलाबचन्द नागर के आवास पर जाकर उनके पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की साथ ही लक्ष्मीपुरा निवासी छोटेलाल भील जिनकी बाढ़ की चपेट में आने से नाले में बहकर अस्वामयिक मृत्यु होने पर शोक व्यक्त किया तथा मौके पर ही प्रशासन से वार्ता कर पीडित परिवार को आर्थिक सहायता अतिशीघ्र उपलब्ध करने एवं परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का आग्रह किया। विधायक सिंघवी ने बताया कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में सैकड़ों व्यक्तियों के कच्चे व पक्के मकान ध्वस्त हो गये हैं तथा हजारों बीघा की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, अभी



भी खेतों में पानी भरा हुआ है, जिसके कारण खेतों में फसलो की उपज नहीं हो सकती है। किसानों के पास उपज एवं खाद्य सामग्री पूरी तरह नष्ट हो गई है। कई परिवारों के सामने तो परिवार के भरण पोषण करने की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। विधायक सिंघवी ने सरकार से मांग की है कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का अतिशीघ्र सर्वे कराकर पीडित व्यक्तियों को तत्काल मुआवजा उपलब्ध कराया जाये। विधायक सिंघवी के साथ

छीपाबड़ौद प्रधान नरेश मीणा, वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम कचनारिया, सरपंच रामकल्याण गुर्जर, सरपंच संजय पोरता, सरपंच रामविलास कालाटोल, सरपंच भवर्लाल दीगोद जागीर, पूर्व सरपंच प्रेम तिवारी, ओम खण्डेलवाल, रामरतन बरसात, हेमन्त दोलिया, पूर्व प्रधान उदयसिंह मीणा, पंचायत समिति सदस्य हुकमचंद नागर, मुरली मेहरा, अमित शर्मा एवं महेंद्र नागर दीगोद जागीर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कोटा-बूंदी में राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट की खामियां होंगी दूर

लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश पर कोटा पहुंचा सेव लाइफ फाउंडेशन का प्रतिनिधिमंडल

हिलव्यू समाचार

कोटा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर संसदीय क्षेत्र कोटा-बूंदी में राजमार्गों को सुरक्षित बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इन राजमार्गों पर सड़क हादसों का प्रमुख कारण बने ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर खामियां दूर की जाएगी। बिरला की पहल पर देशभर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय के निर्देशन में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था सेव लाइफ



सदस्य व सेव लाइफ फाउंडेशन के सीइओ पीयूष तिवारी ने बताया कि ब्लैक स्पॉट पर रतार सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। फाउंडेशन ग्राउंड सर्वे और डेटा एनालिसिस के माध्यम से रिपोर्ट तैयार कर केंद्र व राज्यों को

उपलब्ध कराती है ताकि रिपोर्ट के आधार पर ब्लैक स्पॉट खत्म करने की दिशा में काम हो। सेव लाइफ फाउंडेशन कोटा और बूंदी में ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर इनकी खामियां दूर करने के सुझाव के साथ विस्तृत रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय और मंत्रालय को सौंपी। इस दिशा में टीम ने बुधवार को एनएचआई के सहयोग से कोटा में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर 6 स्थानों चिन्हित ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण किया गया।

प्रभावित नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक ने किया जलभराव क्षेत्रों का निरीक्षण

हिलव्यू समाचार

कोटा। गत सप्ताह कोटा में भारी वर्षा हुई। पानी निकासी की व्यवस्था के साथ प्रभावित नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लगातार वर्षा एवं कोटा बैराज से पानी की निकासी के कारण शहर के नीचले इलाकों एवं बस्तियों में जल भराव की स्थिति बन गयी। इन क्षेत्रों से नागरिकों को जिला प्रशासन द्वारा बनाये गये अस्थाई आश्रय स्थलों पर पहुंचाकर भोजन एवं आवास की व्यवस्थाएं की गयीं। जिला कलक्टर ओपी बुनकर एवं पुलिस अधीक्षक शहर केशर सिंह ने जलभराव क्षेत्रों का दौरा कर पानी निकासी एवं प्रभावित क्षेत्रों से नागरिकों को सुरक्षित पहुंचाने का जायजा लिया। जिला कलक्टर ने प्रभावित क्षेत्रों में पानी निकासी के लिए नगर निगम एवं नगर विकास न्यास की टीम को त्वरित कार्यवाही



कर व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने स्थलों पर पहुंचाकर भोजन, आवास आदि ऐसे क्षेत्रों से नागरिकों को अस्थाई आश्रय व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने

चम्बल के आस-पास की बस्तियों में दौरा कर नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का आह्वान किया।

पुलिस अधीक्षक शहर ने प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगर निगम की टीम को संयुक्त रूप से भ्रमण कर नागरिकों को प्राथमिकता से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिये।

यहां किया निरीक्षण

अधिकारियों द्वारा कुन्हाडी स्थित बापू बस्ती, बालिता रोड, नयापुरा स्थित वाल्मीकि बस्ती, नयापुरा बस स्टैंड, खण्ड गावडी, नंदा जी बाडी, रेल्वे स्टेशन, संजय नगर, रेल्वे कॉलोनी, काला तालाब क्षेत्र के आवासीय कॉलोनियों, जवाहर नगर, देवली अरब, रायपुरा सहित शहर के पानी भराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण कर पानी निकासी के लिए नगर निगम की



अनियोजित विकास के चलते पूरा शहर जलमग्न, लोग घरों में क़ैद रहने को हुए मज़बूर: गुंजल

हिलव्यू समाचार

कोटा। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने बयान जारी करते हुए कहा कि अनियोजित विकास के चलते चंद घंटों की बारिश में ही पूरा शहर जलमग्न हो गया। शहर की कोई गली, कोई मुख्य मार्ग ऐसा नहीं बचा जहां जलभराव नहीं हुआ हो। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया। जिससे उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही शहरवासी घरों में क़ैद होने को मज़बूर हो गए। गुंजल ने कहा कि शहर को टूरिज्म सिटी

बनाने व शहर के चहुमुखी विकास का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार व मंत्री के दावों की चंद घंटों की बरसात में ही पोल खुल गई। शहर का नवनिर्मित जेडीबी चौराहा, नयापुरा चौराहा, गोरबिया बावड़ी चौराहा, पॉलिटेक्निक चौराहा सहित सभी चौराहों पर जलभराव नहीं हुआ हो। अंटाघर व गोरबिया बावड़ी अंडरपास में पानी भरने से यातायात प्रभावित हो गया। वहीं करोड़ों रुपय खर्च कर बनाए जा रहे रिवरफ्रंट के हालात भी किसी से छुपे नहीं हैं।

हिलव्यू समाचार में विज्ञापन एवं खबरों के लिए सम्पर्क करें...

हरीश श्रीवास्तव

सह संपादक, छबड़ा

+9461846059, 7976561127

असलम रोमी पत्रकार

विशेष संवाददाता कोटा

+91 99283 50279, 7976561127

एक नज़र

सृष्टि द वूमैस क्लब ने मनाया नंदोत्सव और सीनियर सिटीजन डे



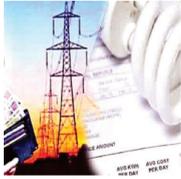
हिलव्यू समाचार

जयपुर। सृष्टि द वूमैस क्लब ने सृष्टि लीनिंग क्लब के साथ गांधीनगर स्थित एक होटल में बहुत ही धूमधाम के साथ नंदोत्सव और सीनियर सिटीजन डे मनाया। क्लब फाउंडर मधु सोनी ने बताया कि इस अवसर पर क्लब की सभी महिलाएँ बिल्कुल यशोदा मां की तरह सज कर आई साथ में अपने लड्डू गोपाल को भी सजा कर लाई। अर्चना शर्मा की भजन मंडली ने भक्ति रस से सारा माहौल कृष्णमय कर दिया। क्लब उपाध्यक्ष कमलेश सोनी ने बताया कि बच्चे राधा कृष्ण बनकर आए। सभी सखियों ने हांडी का केक काटा एवं नृत्य किया। कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई में सभी ने खूब लूट मचाई और देही हांडी फोड़ कर नन्दे कान्हा के साथ उपस्थित सभी क्लब

मेंबरस एवं सम्मानित मेहमानों ने माखन मिश्री का आनंद लिया। इस अवसर पर क्लब के सभी सीनियर सिटीजन नीलिमा, बुजेश पवार, रेनु अग्रवाल सहित 11 महिलाओं का सम्मान साड़ियाँ भेंट देकर किया गया। नंदोत्सव में अतिथि के रूप में श्रीमती पुष्पेंद्र भारद्वाज, स्नेहलता भारद्वाज, शांति भटनागर का सम्मान किया गया। क्लब फाउंडर मधु सोनी, उपाध्यक्ष कमलेश सोनी, सचिव रेनु खुराना, संरक्षक निशा सोनी, मंजू शर्मा अंजू वर्मा, सुनीता सोनी सांस्कृतिक मंत्री, नीलू गुप्ता, पूर्णिमा सोनी, मीनू शर्मा, कल्पना शर्मा इत्यादि का सभी ने हौसला बढ़ाया। अंत में माखन मिश्री का भोग एवं आरती के बाद सभी को प्रसादी वितरित की गई। कमलेश सोनी ने सभी का आभार प्रकट किया।

बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही लग सकता है बिल बढ़ने का झटका

जयपुर (हिलव्यू समाचार)। प्रदेश में आम उपभोक्ताओं की बिजली की दरों में जल्द ही बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस संबंध में तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर की गई है। इसमें बिजली के स्थाई शुल्क में बढ़ोतरी के साथ ही प्रति यूनिट बिजली की दरों में भी करीब दो फीसदी तक की बढ़ोतरी किए जाने का निवेदन किया गया है। प्रदेश की जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक राजस्व याचिका दायर की गई है। इस याचिका में आगामी राजस्व घाटे को देखते हुए बिजली के स्थाई शुल्क और प्रति यूनिट ऊर्जा शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। **हितधारक ने मांगी थी जानकारी:** बिजली कंपनियों की ओर से वर्तमान वित्तीय वर्ष में बिजली की दरों को लेकर किए जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन को लेकर हितधारक समता पावर के निदेशक बीएम सनाहद की ओर से वितरण कंपनियों से जानकारी मांगी गई थी।



इतना हो रहा घाटा

याचिका में तीनों वितरण कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 वित्तीय घाटा या राजस्व का अंतर 4582 करोड़ रुपए और वर्ष 2022-23 वित्तीय या राजस्व का अंतर 4861 करोड़ रुपए बताया गया है। दोनों सालों में कंपनियों का कुल घाटा 9443 करोड़ रुपए रहेगा।

इतनी हो सकती है बढ़ोतरी: प्रदेश में विद्युत कंपनियों की ओर से कृषि, धरतू, अधरतू, उद्योग श्रेणियों के लिए अलग-अलग प्रति यूनिट का टैरिफ जारी किया हुआ है। इस टैरिफ में दो फीसदी उर्जा शुल्क की बढ़ोतरी से प्रति यूनिट बिजली में 15 से तीस पैसे तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है।

दिल्ली में 'इन्वेस्टर्स मीट एंड एमओयू साइनिंग सेरेमनी' राज्य सरकार और निवेशकों के बीच 69,789 करोड़ के एमओयू



■ जयपुर में 7-8 अक्टूबर, 2022 को आयोजित होगा 'इन्वेस्ट राजस्थान' ■ मुख्यमंत्री ने कहा... निवेशक राज्य में औद्योगिक विकास के लिए दें सुझाव हिलव्यू समाचार

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र स्थापना को लेकर अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इससे निवेशकों को राज्य में निवेश करने में आसानी हुई है। यहां निवेशकों की समस्याओं को सुनना और प्रतिबद्धता के साथ उनका समयबद्ध निस्तारण करना राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। वर्तमान में रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, सौर ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा विकास आदि में भारी निवेश करने वाले कानून-व्यवस्था, बेहतर निवेशकों के लिए उपलब्ध अनुकूल नीतिगत ढांचे से



पहली पसंद बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रीको द्वारा राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। एनसीआर ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा विकास आदि में भारी निवेश करने वाले कानून-व्यवस्था, बेहतर निवेशकों के लिए उपलब्ध अनुकूल नीतिगत ढांचे से

आयोजित एमओयू साइनिंग सेरेमनी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज हुए एमओयू सहित अब तक करीब 11 लाख करोड़ के एमओयू एवं एलओआई हो चुके हैं। राजस्थान में सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधता के साथ-साथ अब निवेशकों की भी विविधता है। रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीप्रोसेसिंग, माइनिंग, ई-व्हीकल, सेरेमिक तथा ग्लास के क्षेत्र में निवेश इसके प्रमाण हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफ्स के तहत निवेशकों को उनकी जरूरत के अनुसार पैकेज दिए जा रहे हैं। एमएसएमई-2019 के तहत नवीन उद्यम इकाइयों को 3 साल तक किसी सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं होने के साथ वन स्टॉप शॉप प्रणाली से सभी सरकारी स्वीकृतियां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, एमएसएमई एवं रिफ्स सहित प्रत्येक सेक्टर के लिए पॉलिसी बनाई गई है। गहलोत ने कहा कि जोधपुर जिले में 14 हजार एकड़ में फैला विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क है। उन्होंने कहा कि जब में पहली बार मुख्यमंत्री बना, उस समय जैसलमेर में सिर्फ 2 मेगावाट विंड एनर्जी थी, वर्तमान में 5000 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए सभी निवेशकों के सुझाव आमंत्रित हैं। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने कहा कि डीएफसी कॉरिडोर एरिया का 40 प्रतिशत और डीएमआईसी का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा राज्य से गुजरता है। सबसे बड़े राज्य और स्ट्रेटिजिक स्थिति के चलते राजस्थान

निवेश की विशाल संभावनाएं प्रदान करता है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में वन स्टॉप शॉप, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019, फैसिलिटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट जैसे अनेक कदम उठाए हैं। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने कहा कि निवेश के लिए राजस्थान सर्वश्रेष्ठ स्थान बन गया है। राजस्थान को अब अक्सर की भूमि कहा जाता है। राजस्थान में एक ही पोर्टल पर निवेशकों को विभिन्न अनुमोदन प्राप्त हो रहे हैं। राज्य सरकार जयपुर में नए कार्गो कॉम्प्लेक्स, एक्सपोर्ट क्लियरेंस के लिए नवीन फैसिलिटी और उदयपुर में नए कार्गो कॉम्प्लेक्स, बीकानेर में आईसीडी के साथ राजस्थान के विकास की दिशा में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में राज्य सरकार और निवेशकों के बीच 69,789.93 करोड़ रुपए के एमओयू हुए। इससे राज्य में कुल 11846 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इनमें अक्टू पावर द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोजेक्ट पर लगभग 40,000 करोड़ रुपये, ओ2 पावर एनर्जी पीटीई द्वारा अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा सेक्टर में 25,000 करोड़ रुपये, असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड द्वारा 1400 करोड़ रुपये, सेंट गोबेन द्वारा 1000 करोड़ रुपये के निवेश से फ्लोट ग्लास मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना के प्रस्ताव हैं। वरुण बेवरेज लिमिटेड द्वारा 636 करोड़ रुपये की कार्बोनेटेड सॉफ्ट-ड्रिंक्स, फ्रूट-जूस एवं पैकेजिंग प्रोडक्ट्स की मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। विप्रो जयपुर में हाइड्रोलिक सिस्टम प्रोजेक्ट में 200 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।

सीआईडी सीबी ने पकड़ी नशे की बड़ी खेप विशाखापट्टनम से 3 करोड़ कीमत का 1205 किलो गांजा लाते तीन तस्कर गिरफ्तार

जयपुर (हिलव्यू समाचार)। राजस्थान पुलिस की सीआईडी सीबी जयपुर की टीम ने चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन थाना क्षेत्र में गुरुवार रात स्थानीय पुलिस के सहयोग से विशाखापट्टनम से ट्रक कन्टेनर में तस्करी कर लाया जा रहा 1205 किलो गांजा बरामद करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार करवाया है। प्लास्टिक की 364 थैलियों में भरकर गांजा ला रहे तस्कर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले और हरियाणा में स्थानीय तस्करों को इसे सप्लाई करने वाले थे। पकड़े गए गांजा की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए आंकी गई है। डाक पार्सल लिखे कंटेनर से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही थी। एडीजी क्राइम डॉ विप्रकाश मेहरडा ने बताया कि तस्कर राजू पुरी गोस्वामी पुत्र कैलाश पुरी निवासी वार्ड नंबर 3 भगवानपुर थाना मांडल जिला भीलवाड़ा जिले में निवासी पुत्र प्रहलाद (23) निवासी दादा थाना सायला जिला जालौर एवं प्रहलादराय सोनी पुत्र राजमल (54) निवासी सुनारा का मोहल्ला भागवानपुर थाना मांडल जिला भीलवाड़ा को गिरफ्तार किया गया है। इन तस्करों



की हर गतिविधियों पर सीआईडी सीबी की टीम पिछले दो-तीन महीनों से नजर रख रही थी। इसी दौरान बुधवार को विशाखापट्टनम से भीलवाड़ा भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के इनपुट मिले। आसूचना से प्राप्त इनपुट पर सीआईडी क्राइम ब्रांच स्पेशल टीम प्रभारी डीएसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के सुपरविजन एवं पुलिस निरीक्षक राम सिंह नाथावत के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल शंकर दयाल शर्मा और बाल में बैठे जितेंद्र प्रोहित और प्रहलादराय सोनी से पूछताछ की तो वे चबरा गये। सबूतों से पूछताछ की गई तो उन्होंने कंटेनर में प्लास्टिक की वेस्ट बोतलों की आड़ में विशाखापट्टनम से गांजा तस्करी कर लाना बताया। होकर कपासन की ओर आ रहे हैं। कपासन थाना क्षेत्र में नाकाबंदी में पकड़ा ट्रक कंटेनर: एडीजी क्राइम ने बताया कि सीआईडी सीबी की टीम ने इस सूचना पर गुरुवार रात को थानाधिकारी कपासन फूलचंद के सहयोग से थाना क्षेत्र के रेलिया कॉलपुरा रोड पर स्वामी विवेकानंद राजकीय स्कूल के पास नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान संधिध कंटेनर को रकवाया गया। चालक सीट पर बैठे राजू पुरी और बाल में बैठे जितेंद्र प्रोहित और प्रहलादराय सोनी से पूछताछ की तो वे चबरा गये। सबूतों से पूछताछ की गई तो उन्होंने कंटेनर में प्लास्टिक की वेस्ट बोतलों की आड़ में विशाखापट्टनम से गांजा तस्करी कर लाना बताया।

364 प्लास्टिक की थैलियों से जल्द किया 1205 किलो गांजा: रात होने एवं अंधेरा होने से तीनों अभियुक्तों को डिटेनर कंटेनर को थाना परिसर लाया गया जहां तलाशी ली गई आरोपियों के पास तीन कोपैड मोबाइल, 2 एंड्रॉइड मोबाइल कुल 900 रुपये एवं कंटेनर में प्लास्टिक की वेस्ट बोतलों के बीच और आगे की तरफ छुपा कर 364 प्लास्टिक की थैलियों में भरा 1205 किलो 600 ग्राम गांजा मय बरदाना मिला। भीलवाड़ा और हरियाणा में सप्लाई होना था गांजा : अवैध मादक पदार्थ गांजा से भरे ट्रक कंटेनर को जप्त कर तीनों तस्करों को एनडीपीएस एक्ट के तहत कपासन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। अग्रिम अनुसंधान के लिए प्रकरण गंधार पुलिस को सौंपा गया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि ट्रक कंटेनर में तस्कर राजू पुरी और प्रह्लाद राय सोनी का माल था। इसकी सप्लाई भीलवाड़ा और हरियाणा में की जानी थी। इन दोनों तस्करों के विरुद्ध पूर्व में भी गांजा तस्करी के प्रकरण दर्ज हुए हैं।

जयपुर म्यूजिक फेस्टिवल 2022 का आयोजन सम्पन्न



हिलव्यू समाचार। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों की शृंखला में जयपुर संगीत महाविद्यालय द्वारा जयपुर म्यूजिक फेस्टिवल 2022 का जवाहर कला केन्द्र के रंगमंच सभागार में आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सम्माननीय अतिथि डा अर्चना शर्मा जी तथा वी एल टी ग्रुप की चैयरमैन श्रीमति ललिता वैष्णव जी तथा समारोह अध्यक्ष राजेश मेहता तथा जयपुर संगीत महाविद्यालय के निदेशक राम शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर रंगारंग संख्या का शुभारंभ किया। जयपुर संगीत महाविद्यालय की ओर से निदेशक श्री राम शर्मा, कोषाध्यक्ष श्रीमती रानी शर्मा ने अतिथिगण का माल्यार्पण कर अभिनन्दन किया। वर्ष 2016 से संगीत के उन्नयन और विकास के प्रति समर्पित जयपुर संगीत महाविद्यालय ने अबतक 4000 विद्यार्थियों को संगीत की विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दिया है। कार्यक्रम का प्रायोजन, वी एल टी ग्रुप ने किया। समारोह में जयपुर संगीत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने गायन वादन नृत्य की विभिन्न

विधाओं से समां बाँधा। समारोह में सुप्रसिद्ध नर्तक श्री विशाल कृष्णा ने अपनी मनोहरी प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीता साथ ही भरतनाट्यम और राजस्थानी लोक नृत्य को प्रस्तुति ने सभागार का गुंजायमान बना दिया इसी शृंखला में मत कर माया को अभिमान एवम जल को बचाने के लिए जलगीत के द्वारा उसकी महत्ववस्ता बताई गयी। मुख्य अतिथि माननीय महाविद्यालय जी तथा विशिष्ट अतिथि गण ने प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए समाज में कला एवम संस्कृति के विकास हेतु संगीत महाविद्यालय के प्रयत्नों को सराहा। समारोह का मंच संचालन सुप्रसिद्ध कवि तथा वरिष्ठ रंगकर्मी राजेश आचार्य ने किया। समारोह के दौरान जयपुर क्षेत्र के सात युवा कलाकारों को भी सम्मानित किया गया जिनमें रीना प्रधान, चेतन जवड़ा, भवदीप जवड़ा, नीलम रावत, प्रीति भार्गव, विशाल कृष्णा (बनारस) को नृत्य शिरोमणि अवार्ड 2022 एवं अजय चौधरी को सुरम्यणी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संगत कलाकारों में सितार पर ही हर शरण भट्ट, सारी पर अमीर खान, तबला पर अमीर खान, अभिषेक मिश्रा (बनारस), गायन पर जयवर्धन दाधीच ने अहम भूमिका निभाई।

ग्रेटर निगम के तीन पार्षद बर्खास्त

हिलव्यू समाचार। राज्य सरकार ने नगर निगम ग्रेटर में निर्लंबित तीन पार्षदों को बर्खास्त कर दिया है। इन्हें आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ मारपीट, धक्का-मुक्की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का दोषी मानते हुए निर्लंबित किया गया था। आदेशों के मुताबिक वाई 72 से भाजपा के पार्षद पारस जैन, वाई 39 से अजय सिंह और वाई 103 से निर्दलीय शंकर शर्मा को बर्खास्त किया गया है। ये तीनों न्यायिक जांच में भी दोषी पाए गए थे। वहीं मेयर सोम्या गुजरं पर भी न्यायिक जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के बाद सरकार एक्शन लेगी। **रिक्त सीटों पर पुनः होंगे चुनाव:** राज्य सरकार से जारी आदेशों के बाद अब ये तीनों पार्षद अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इन तीनों पार्षदों को अब चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। इनके हटने के बाद खाली हुई सीट पर दोबारा चुनाव करावा जाएगा।

राजस्थान आवासन मण्डल की एक और शानदार उपलब्धि

मानसरोवर एवं प्रताप नगर चौपाटी में पहले 5 माह में 6.10 लाख लोगों के फुट-फॉल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दी मान्यता



पुदुचेरी की पूर्व उप राज्यपाल डॉ. किरण बेदी ने दिया सम्मान मण्डल की सफलता सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल - आवासन आयुक्त

हिलव्यू समाचार। जयपुर। आवासन मण्डल आयुक्त श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान आवासन मण्डल ने अपने कीर्तिमानों की कड़ी में एक और शानदार उपलब्धि हासिल की है। मण्डल द्वारा विकसित मानसरोवर एवं प्रताप नगर चौपाटी में नवम्बर, 2021 से मार्च, 2022 के दौरान पहले 5 माह में 6 लाख 10 हजार 670 लोगों के प्रवेश (फुट-फॉल) को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अन्तर्राष्ट्रीय कीर्तिमान के रूप में मान्यता दी है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से इन्दौर के होटल जे.डब्ल्यू. मैरियट में सोमवार को आयोजित समारोह में पुदुचेरी की पूर्व उप राज्यपाल



डॉ. किरण बेदी और उदयपुर पूर्व राजधराने के सदस्य श्री लक्ष्मण सिंह मेवाड़ ने मण्डल को यह पुरस्कार प्रदान किया। आवासन मण्डल की ओर से उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय) श्री विजय अग्रवाल ने प्रमाण-पत्र और पुरस्कार ग्रहण किया।

इस अनूठी उपलब्धि पर आवासन आयुक्त श्री पवन अरोड़ा ने दोनों चौपाटियों को विकसित एवं संचालित करने वाली मण्डल की टीम, चौपाटियों के दुकानदारों, लाइव बैंड परफॉर्मेंस देने वाले आर्टिस्टों आदि को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों से मानसरोवर एवं प्रताप नगर चौपाटी न केवल जयपुरवासियों बल्कि यहां आने वाले लाखों देशी-विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केन्द्र बन गई है। इस समारोह में स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, बांग्लादेश, मॉरिशस, नेपाल सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि तथा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रेसिडेंट एवं

सीईओ श्री संतोष शुक्ला एवं हेड ऑफ यूरोप श्री विलहेम जेजलर भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व वर्ष 2020 में बुधवार नीलामी उत्सव के तहत मात्र 12 दिन में 185 करोड़ रुपये मूल्य की 1213 सम्पत्तियों के विक्रय तथा वर्ष 2019 में मात्र 35 कार्यदिनों में 1010 मकान बेचने की उपलब्धि को भी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लॉन्च ने कीर्तिमान के रूप में स्थापन दिया था। बीते करीब 3 वर्षों में आवासन मण्डल को इण्डियन बिल्डिंग कांग्रेस, नेशनल रियल एस्टेट काउंसिल नई दिल्ली, स्कॉच ग्रुप आदि संस्थाओं से कई पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं।

एक नज़र

Gender Neutral Rape Laws: Not As Simple As You Might Think

ADITYA RAJ

After the Nirbhaya Rape case in Delhi, a committee led by Justice Verma, a former Chief Justice of the Supreme Court, was established in December 2012 to make recommendations for amendments to the Criminal Law that would expedite the legal process and strengthen punishment for those found guilty of sexual assault against women. Justice Leila Seth, a former High Court judge, and Gopal Subramaniam, a former Solicitor



General of India, were the other members of the Committee.

On January 23, 2013, the Committee submitted its report. It included suggestions for changes to the law pertaining to rape, sexual assault, trafficking, child sexual abuse, victim medical examinations, police, and electoral and educational reforms

but the government rejected their recommendations and passed legislation making rape a crime against both sexes, making it gender neutral.

What followed was a lot of backlash from feminist groups. It is important to note that gender neutrality was not the only reason why there was a backlash, but also because they did not take any of the recommendations from the Committee, including recognising marital rape and keeping the age of consent at 16. Marital rape is still, even in 2022, not recognised by our constitution.

Prominent women's rights advocate Flavia Agnes also voiced concern against the bill, "I oppose proposal to make rape laws gender-neutral," she also added that women's groups had also protested against gender neutral Child Sexual Abuse laws.

Do boys not get abused?

India had pledged to safeguard its children from all types of sexual exploitation and abuse when it ratified the United Nations Convention on the Rights of the Child in 1992. The first extensive government-sponsored research study to evaluate the scope and form of child abuse in India was commissioned as a result of growing concerns about female infanticide, child rapes, and institutional abuse of children. Shockingly, a government-commissioned survey revealed that more than 53% of Indian youngsters experience sexual abuse or assault. With almost half of the victims of child sexual abuse being boys.

In 2012, Delhi advocate Vrinda Grover said: "Why should rape laws be gender neutral? There are no instances of women raping men."

Do men not get raped by women?

There is a misconception that men are more likely to be raped by other men. This misconception originates from rape statistics in the USA. In truth, the States' definition of rape is flawed, it does not consider "made to penetrate" as rape. For male victims, the sex of the perpetrator varied by the type of sexual violence experienced.

THE MAJORITY OF MALE RAPE VICTIMS (93.3%) REPORTED ONLY MALE PERPETRATORS.

FOR THREE OF THE OTHER FORMS OF SEXUAL VIOLENCE, A MAJORITY OF MALE VICTIMS REPORTED ONLY FEMALE PERPETRATORS: BEING MADE TO PENETRATE (79.2%), SEXUAL COERCION (83.6%), AND UNWANTED SEXUAL CONTACT (53.1%).

FOR NON-CONTACT UNWANTED SEXUAL EXPERIENCES, APPROXIMATELY HALF OF MALE VICTIMS (49.0%) REPORTED ONLY MALE PERPETRATORS AND MORE THAN ONE-THIRD (37.7%) REPORTED ONLY FEMALE PERPETRATORS.

5,451,000 men reported being 'forced to penetrate' in their lifetime while 1,581,000 men were 'penetrated by someone else', hence around four times more men are made to penetrate than that are penetrated by someone else in the US. If 'made to penetrate' is also considered as rape, which it is, then the majority of male rape victims are raped by women.

Unfortunately we have no data at all for male rape victims in India. Hence the situation can only be assessed based on speculations and analogies. The countries are on extremely different stages of gender equality, but it should give us some context.

Another reason why feminists opposed gender neutral rape laws is because they believed that if the laws are not gender-specific, the perpetrator can file a counter-case against the victim to mislead the court. Intimidating the victims into taking their complaint back.

Instead they argued in favour of the perpetrator being gender specific and the victim being gender neutral.

There is little evidence to support or disprove this claim, however this is an opinion shared by many lawyers and judges, including justices from the Supreme Court. Holding the view that the Indian society is not yet ready for gender neutral rape laws. They believe that there should be separate laws, instead, where complaints can be filed against women when there is a clear power dynamic, such as hostel wardens, or teachers and so on.

They hold that the men who benefit from gender neutral rape laws are much fewer than the women who will have to suffer. Female on Male rape victims are likely to be statistically quite small. On the other hand around 3 million women face sexual violence every year and 99% of those cases are never reported.

This is the trolley problem. If rape laws are made gender neutral then it will give a course of justice to male rape victims, but will also

harm female victims by giving more legal avenues to the rapist. On the other hand, if the rape laws are gender specific, then it will deny justice to female on male rape victims. And as is the trolley problem, you run over the side with fewer bodies ...

... right?

Well however you may choose to answer this moral paradox, the centre repealed the bill. According to the Indian penal code, men cannot be raped. Not even by other men; though they do have a legal course to justice via sodomy laws. When in 2018 activists tried to make rape laws gender neutral once again, the centre said that rape laws cannot be gender neutral after 'consultation with Women's Groups'.

This topic is still a matter of debate amongst feminist groups; with the younger and inter-sectional generation being in favour of gender neutral laws, while the older and experienced one argues against it, holding the view that India is just not ready.

गडकरी ने आलोचकों पर साधा निशाना, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

हिलव्यू समाचार

नई दिल्ली। डूक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को अपने आलोचकों और मीडिया के एक वर्ग पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए उनके बयानों को गलत तरह से पेश किया जा रहा है। अपने बयानों को लेकर अक्सर खबरों में रहने वाले गडकरी को पिछले सप्ताह भाजपा संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया था। गडकरी ने ट्वीट किया, एक बार फिर मुख्याधार के मीडिया, सोशल मीडिया के एक वर्ग और कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक फायदे के लिए मेरे खिलाफ घृणित और मनगढ़ंत अभियान जारी रखने के प्रयास किए जा रहे हैं और सार्वजनिक समारोहों में मेरे बयानों को बिना सही संदर्भ के पेश किया जा रहा है। गडकरी ने मंगलवार को एक पुस्तक विमोचन समारोह में दिए गए अपने भाषण के यूट्यूब लिंक को ट्वीट किया जिसका सोशल मीडिया



पर इस्तेमाल किया जा रहा है। गडकरी ने भाजपा अध्यक्ष जे पी नट्टा और प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए ट्वीट किया, मैं ऐसे तत्वों के इस तरह के दुर्भावनापूर्ण एजेंडे से कभी परेशान नहीं हुआ लेकिन

गडकरी का दावा

ऐसे तोड़ा मरोड़ा मेरा बयान

अक्सर पार्टी और संगठन से जुड़ी कहानियां सुनाने वाले गडकरी ने पुस्तक विमोचन समारोह में एक पुरानी घटना का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के एक गांव में सड़क बनाने का जिम्मा लिया था और संबंधित अधिकारी को कहा था कि अगर वह उनके साथ खड़ा रहा तो सही है लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने इस बातचीत का जिक्र करते हुए कहा, मुझे नतीजों की चिंता नहीं है लेकिन मैं यह काम करूंगा। अगर मुमकिन है तो मेरे साथ रहो, वरना मुझे कोई परेशानी नहीं है। इस बयान को सोशल मीडिया पर इस तरह से पेश किया जा रहा है कि गडकरी को अपना पद खोने की कोई चिंता नहीं है।

आप नेता संजय सिंह ने किया ट्वीट

आप सांसद संजय सिंह ने वीडियो ट्वीट करके पूछा था कि गडकरी ऐसा क्यों कह रहे हैं। भाजपा में बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। गडकरी का ट्वीट भी गुरुवार को तब आया है जब एक प्रमुख अखबार की खबर में भाजपा के कई वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि पूर्व भाजपा अध्यक्ष को कुछ अलग और सुखियों में रहने वाले बयान देने की प्रवृत्ति के लिए संसदीय बोर्ड से हटाया गया है।

आप ने 20-20 करोड़ रुपए की पेशकश का आरोप दोहराया, कहा...

हरियाणा-पंजाब को मिली स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात

स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक साथ छह मोर्चों पर काम: पीएम

मोहाली/फरीदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हरियाणा और पंजाब के दौरा किया और दोनों राज्यों को एक-एक चिकित्सा केंद्रों की सौगात दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार एक साथ छह मोर्चों पर काम कर रही है और रिपोर्ट निवेश कर रही है। मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करने के बाद मोदी ने कहा कि भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम पिछले आठ साल में हुआ है उतना पिछले 70 वर्षों में भी नहीं हुआ है। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में पीएम ने 6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बने 2,600 बिस्तरों वाले अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल का प्रबंधन माता अमृतानन्दमयी मठ द्वारा किया जाएगा। अस्पताल में शुरूआत में 500 बेड की व्यवस्था रहेगी और अगले पांच वर्षों में इसे चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा।



आरोग्य और आध्यात्म एक दूसरे से जुड़े हुए

पीएम ने फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद कहा कि भारत में आरोग्य और आध्यात्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और देश में कोविड-19 रोगी टीकाकरण अभियान आध्यात्मिक-निजी भागीदारी का सफल उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृता अस्पताल का ये प्रकल्प देश के दूसरे सभी संस्थाओं के लिए एक आदर्श बनेगा। हमारे कई दूसरे धार्मिक संस्थान इस तरह की संस्थाएं चला भी रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद अम्मा के नाम से प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानन्दमयी देवी को मोदी ने झुककर प्रणाम किया तो उन्होंने उनपर गुलाब के फूल बरसाए। उद्घाटन समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय मंत्री व फरीदाबाद के सांसद कृष्ण पाल गुर्जर, माता अमृतानन्दमयी देवी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इन मोर्चों पर हो रहा है काम



पीएम मोदी ने मोहाली में अपने संबोधन में स्वास्थ्य मोर्चे पर कार्यों की चर्चा करते हुए प्रीवेंटिव हेल्थ केयर यानी बीमारी से बचाव को बढ़ावा दिए जाने को पहला और गांवों में छोटे और आधुनिक अस्पताल खोले जाने को दूसरा मोर्चा बताया। उन्होंने शहरों में मेडिकल कॉलेज और शोध वाले बड़े संस्थान खोलना, देश भर में चिकित्सकों और पैरामेडिकल कर्मियों की संख्या बढ़ाना, मरीजों को सस्ती दवाइयां व सस्ते उपकरण उपलब्ध कराने और प्रीवोगिकी का इस्तेमाल करके मरीजों को होने वाली मुश्किलें कम करने को अन्य चार मोर्चे बताया, जिन पर सरकार काम कर रही है।

उन्होंने कहा, इस पर केंद्र सरकार रिपोर्ट निवेश कर रही है... हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, उपस्थित थे। इस अस्पताल का 660 करोड़ रुपए की लागत से टाटा मेमोरियल सेंटर ने निर्माण किया है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत सहायता-प्राप्त संस्थान है। यह अस्पताल तृतीयक स्तर का अस्पताल है, जिसकी 300 बिस्तरों की क्षमता है। यह पूरे क्षेत्र में कैंसर सुविधा और उपचार के लिए केंद्र के रूप में और संगठन में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल इसकी शाखा के रूप में कार्य करेगा।

हिंदी में क्षमा शर्मा समेत 22 भाषाओं के लेखक-लेखिकाएं होंगे पुरस्कृत

दाधीच को राजस्थानी के लिए मिलेगा बाल साहित्य पुरस्कार

एजेंसी। नई दिल्ली

साहित्य अकादमी ने हिंदी में क्षमा शर्मा को बाल साहित्य पुरस्कार तथा भगवंत अनमोल को युवा साहित्य पुरस्कार दिए जाने की बुधवार को घोषणा की। राजस्थानी में विश्वामित्र दाधीच को उनके कविता संग्रह 'माछलयां रा आंसू' के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। कुल 22 भाषाओं के लेखकों-लेखिकाओं को बाल साहित्य पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की है जबकि 23 भाषाओं के लेखक-लेखिकाओं को युवा साहित्य पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने बताया कि क्षमा शर्मा को क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियां के लिए प्रतिष्ठित बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

उर्दू में कमाली को उनके कविता संग्रह 'हैसलों की उड़ान' तथा अंग्रेजी में

साहित्य अकादमी पुरस्कार

राव ने बताया कि हिंदी में अनमोल को उनके उपन्यास 'प्रमेय' के लिए, उर्दू में मकसूद आफ्नाक को उनके कविता संग्रह 'गिरयाह' के लिए और अंग्रेजी में मिहिर वत्स को उनके यात्रा वृतांत 'टेलस ऑफ हजारीबाग' के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

युवा पुरस्कार

कविता संग्रहों के लिए बांग्ला में सुमन पतारी को 'लिखे किछु होय ना' के लिए, पंजाबी में संघु गगन को 'पंजतीले' के लिए और संस्कृत में श्रुति कानितकर को 'श्रीमतीचरित्रम्' के लिए युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

अशिया सत्तार को उनके 'महाभारत फॉर चिल्ड्रन' के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संस्कृत में कुलदीप शर्मा को उनके कविता संग्रह 'सचित्रम् प्रहलिकाशतकम् (अभिनवसंस्कृतप्रहलिका:)' के लिए, राजस्थानी में विश्वामित्र दाधीच

को उनके कविता संग्रह 'माछलयां रा आंसू' के लिए और बांग्ला में जय मित्र को उनके कहानी संग्रह 'चंद्र पांच जोन बोधु' के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। मराठी में संगीता बर्वे को उनके उपन्यास 'पिपूची वही' के लिए सम्मानित दिया जाएगा।





जब नोएडा ट्विन टावर ज़मींदोज़ हो सकता है तो देश की हर अवैध बिल्डिंग ध्वस्त की जा सकती है किंतु सिर्फ़ ईमानदार शासन-प्रशासन और जागरूक जनता की इच्छा शक्ति पर

दोनों सुपरटेक ट्विन टावरों को क्यों गिराया जा रहा है?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन टावरों को गिराने की कार्रवाई की जा रही है।

दरअसल इन टावरों को निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर किया गया था। बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने का खामियाजा यह टावर कम्पनी भुगत रही है। नोएडा के सेक्टर-93 स्थित 40 मंजिला ट्विन टावरों का निर्माण 2009 में हुआ था। सुपरटेक के दोनों टावरों में 950 से ज्यादा फ्लैट्स बनाए जाने थे लेकिन बिल्डिंग के प्लान में बदलाव करने का आरोप लगाते हुए कई खरीदार 2012 इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए। इसमें 633 लोगों ने फ्लैट बुक कराए थे जिनमें से 248 रिफंड ले चुके हैं और 133 दूसरे प्रोजेक्ट्स में शिफ्ट हो गए लेकिन 252 ने अब भी निवेश किया हुआ था। साल 2014 में नोएडा प्राधिकरण को जोरदार फटकार लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्विन टावर को अवैध घोषित करते हुए उन्हें गिराने का आदेश दे दिया था तब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी किंतु बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गिराने का आदेश दिया।

नोएडा के सेक्टर-93 ए में एक हाउसिंग सोसाइटी के निर्माण के लिए नवंबर 2004 में नोएडा विकास

शालिनी श्रीवास्तव

आज 28 अगस्त दोपहर को ढाई बजे नोएडा के सेक्टर-93 स्थित दोनों सुपरटेक ट्विन टावरों को गिरा दिया जाएगा। इसके पीछे रह रहे रहवासियों को मिल जाएगा आज के बाद धूप और हवा। इन अवैध टावरों के ध्वस्तीकरण की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 32 मंजिला इस इमारत को गिराने के लिए विस्फोटक लगाने का काम भी पूरा हो चुका है। बिल्डिंग को गिराने के लिए लगभग 3,700 किलो विस्फोटक लगाया गया इसीलिए कम्प्रेस-वे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक बंद रहेगा। आसपास की बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को भी कहा गया है कि वे आज दिन भर के लिए अपने घर खाली कर दें।

सुपरटेक ट्विन टावर (T-16 और T-17) का निर्माण

सुपरटेक ट्विन टावर (T-16 और T-17) का निर्माण यूपी अपार्टमेंट्स एक्ट का भी उल्लंघन है।

मूल योजना में बदलाव किया गया था लेकिन बिल्डिंग में मूल योजना के खरीदारों की सहमति नहीं ली थी। जिस एरिया को सुपरटेक ने अपने ग्राहकों को पहले ग्रीन एरिया में दिखाया था, बाद में थोड़े से उसी में दो बड़ा टावर खड़े कर दिए गए। बांशर में ग्रीन एरिया देखकर घर खरीदने वालों के लिए ये एक ठगी से कम नहीं था।

प्राधिकरण सुपरटेक को जमीन का एक भूखंड आवंटित किया। 2005 में न्यू ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियम और निर्देश, 1986 के तहत भवन योजना को मंजूरी मिली जिसके तहत कुल 14 टावरों और एक शापिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। सुपरटेक लिमिटेड ने नवंबर 2005 में एमराल्ड कोर्ट नाम से एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण शुरू किया। जून 2006 में सुपरटेक को उन्हीं

शर्तों के तहत अतिरिक्त जमीन आवंटित कर दी गई। दिसंबर 2006 में 11 फ्लोर के 15 टावरों में कुल 689 फ्लैट्स के निर्माण के लिए प्लान में बदलाव किया गया। 2009 में सुपरटेक ने नोएडा प्राधिकरण के साथ मिलीभगत कर ट्विन टावर का निर्माण शुरू कर दिया। ये टी-16 व टी-17 टावर थे।

दोनों टावरों को लेकर स्थानीय रजिस्टर्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने विरोध करना शुरू कर दिया। क्योंकि-

- उनकी सोसाइटी के ठीक सामने जिसे नोएडा अर्थांरिटी ने पहले ग्रीन बेल्ट बताया था, वहां ये विशालकाय टावर खड़े हो रहे थे।
- इन ट्विन टावरों के निर्माण के दौरान अग्नि सुरक्षा मानदंडों और खुले स्थान के मानदंडों का भी उल्लंघन किया गया था।
- इन टावरों के निर्माण के दौरान NBR 2006 और NBR 2010 का उल्लंघन किया गया था। जिसके मुताबिक इन बिल्डिंगों के निर्माण के दौरान पास की अन्य बिल्डिंगों के बीच उचित दूरी का ख्याल नहीं रखा गया था।
- नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC), 2005 को भी ताक पर रखकर इनका निर्माण किया गया। NBC 2005 के मुताबिक ऊंची इमारतों के आसपास खुली जगह का प्रावधान है टावर T-17 से सटे खुली जगह लगभग 20 मीटर होनी चाहिए थी, 9 मीटर का स्पेस गैप उससे काफी कम है।

मामला कोर्ट पहुंचा

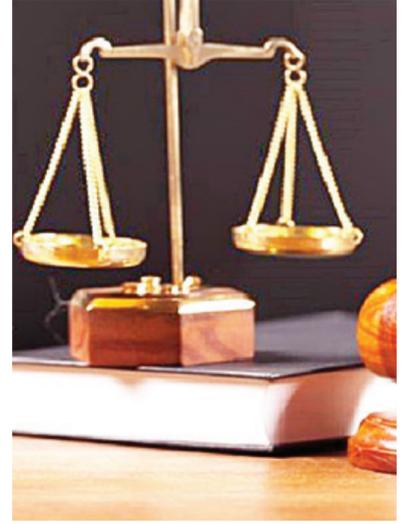
2009 में पूरा मामला कोर्ट पहुंच गया। एमराल्ड कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। 2010 में इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई। मामले में एक्शन न होने पर सोसाइटी के लोग 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। करीब डेढ़ साल तक हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चली। इसके बाद 11 अप्रैल 2014 में हाईकोर्ट ने विवादित टावर ध्वस्त करने का आदेश दिया। इतना ही नहीं कोर्ट ने आरोपी नोएडा अर्थांरिटी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही।

सुप्रीम कोर्ट में 7 साल चली सुनवाई

इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में करीब 7 साल तक पूरा मामला चला। 31 अगस्त 2021 को कोर्ट ने सुपरटेक को बड़ा झटका देते हुए रजिस्ट्रार के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने तीन महीने के अंदर दोनों टावर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। हालांकि कुछ कारणों से इसकी तारीख तीन बार आगे बढ़ाई जा चुकी थी।

खरीदारों का भविष्य क्या?

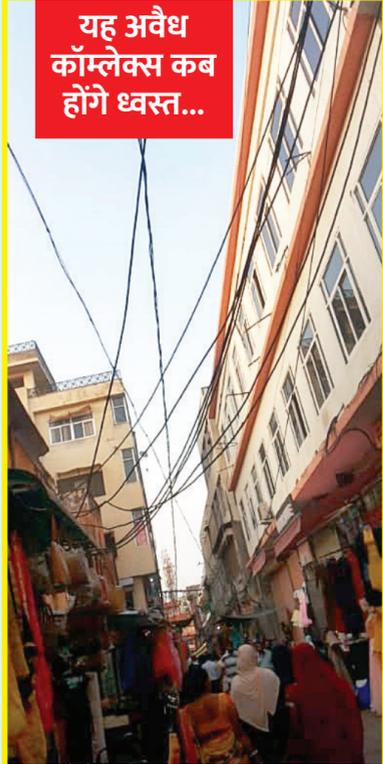
कोर्ट ने अपने फैसले में फ्लैट खरीदारों का भी ध्यान रखा। कोर्ट ने बिल्डर को दो महीने के भीतर 12 फीसदी सालाना ब्याज के साथ ट्विन टावरों में फ्लैट खरीदारों को सभी राशि वापस करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही बिल्डर को रजिस्टर्ड वेलफेयर एसोसिएशन को 2 करोड़ का भुगतान करने का भी निर्देश दिया। मार्च 2022 में सुपरटेक कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने दिवालिया घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि कंपनी पर करीब 1200 करोड़ रुपये का कर्ज है।



ध्वस्तीकरण के दौरान कैसी होगी सुरक्षा व्यवस्था

ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के समय आपातकालीन सेवाओं को भी मौके पर तैनात किया जाएगा। एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस फिरेट स्थापित की जाएगी। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, पीएसओ और फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी व अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही एक डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी और इंसपेक्टर रैंक के पांच अफसरों को ध्वस्तीकरण के दौरान मौके पर तैनात करने की योजना बनाई गयी है।

यह अवैध कॉम्प्लेक्स कब होंगे ध्वस्त...



लगातार 3 साल से मनीराम जी की कोठी सहित 143 अवैध कॉम्प्लेक्सों के ध्वस्तीकरण के राजस्थान हाईकोर्ट आदेश की अवमानना कर रहा है नगर निगम हेरिटेज और डीएलबी

मनीराम जी की कोठी सहित 143 आवासीय हवेलियों में व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों के अवैध निर्माण के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने ध्वस्तीकरण का आदेश 18 सितंबर 2019 को पारित किया। जिसमें तीन सूचियों में इन 143 अवैध भवनों के नाम पते सहित नगर निगम हेरिटेज जयपुर को ध्वस्त करने हेतु पाबंद भी किया गया किंतु पिछले लगभग 3 साल से उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश की अवमानना नगर निगम हेरिटेज जयपुर लगातार कर रहा है। डीबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 15 318/ 2013 सुओमोटो बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के माध्यम से अवैध कॉम्प्लेक्सों की सूचियां जिनका ध्वस्तीकरण किया जाना था वे लगातार हिलव्यू समाचार में प्रकाशित की गई हैं। स्वायत्त शासन हो या प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही अब तक नहीं की गई है।

बल्कि इस बार प्रशासन शहरों के संग अभियान में ध्वस्तीकरण सूची में दर्ज 143 अवैध कॉम्प्लेक्सों में से 421, देना बैंक के सामने, मनीराम जी की कोठी का रास्ता जौहरी बाजार, जयपुर एवं भूखण्ड संख्या 2811 ची वालों का रास्ता जौहरी बाजार, जयपुर ने अवैध पट्टा आवेदन कर ही दिया था जिसकी सार्वजनिक आपत्ति सूचना निगम द्वारा प्रकाशित की गई। अगर जागरूक नागरिक अनिल पायशर द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं की जाती तो क्या इन अवैध भवनों के आवेदकों को पट्टा मिल जाता?

क्या जयपुर कॉलेज नाना जी की हवेली को पाँच मंजिला निर्माण की अनुमति है?



रूपसिंह जी की हवेली पर जयपुर कॉलेज का कब्जा

नाना जी की हवेली जो कि भूखंड संख्या 967 चौकड़ी विषयेश्वर जी, चौड़ा रास्ता जयपुर की एक जानी मानी हवेली रही है। जो वर्तमान में जयपुर कॉलेज के रूप में अपनी पहचान लिए हुए है। इसकी वास्तविक पहचान उसके शिल्प, नक्काशी, पारम्परिक कला और शकल में समाई है लेकिन इस हेरिटेज विषय धरोहर को ध्वस्त कर

नए रूप में निरन्तर बिना किसी रोक-टोक के ढाला जा रहा है। इसी के साथ-साथ भवन रेखा से आगे सड़क सीमा में अतिक्रमण कर पाँच मंजिला अवैध निर्माण कर छत ढाल ली गयी है। जहाँ एक ओर उच्च न्यायालय जयपुर के द्वारा स्थानीय निकाय हेरिटेज नगर निगम को व राज्य सरकार को स्पष्ट आदेश पारित किया गया है



कोई अनुमति नहीं सारा निर्माण अवैध है। नाना जी की हवेली वैश्विक धरोहर है और युनेस्को के नियमों के विरुद्ध परकोटे के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाँच मंजिला बन गयी है और तो और रूपसिंह जी की हवेली प्लॉट न.51-52 पर भी कब्जा किया जा चुका है

कि आवासीय भूखंडों पर अवैध व्यवसायिक निर्माण गतिविधि नहीं की जा सकती एवं इस पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स नहीं बनाए जा सकेंगे। उसके बावजूद निरन्तर नवीनीकरण निर्माण हो रहा है बस पहले खुले में हो रहा था अब लोहे की चादर चढ़ा कर हो रहा है। सरकार को हिलव्यू समाचार द्वारा हर तरह से सूचना दी गयी

है कभी खबर प्रकाशित करके, कभी कॉन्फ्रेंस मीटिंग द्वारा, पीडिडि स्थानीय नागरिकों व पीडिडि दुकानदारों की पीड़ा को प्रकाशित कर, सोशल मीडिया द्वारा लेकिन सरकारी रजामंदी इस अवैध निर्माण में हो तो कौन सुनेगा आम जनता की पीड़ा?

ओझा जी की हवेली मालिकों का सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़, ओवर राइटिंग और फ़र्जी सील लगाने का अवैध मामला



क्या WTP को जेडीए से अनुमति मिली थी सड़क क्रॉस करते हुए छत ढालने की?

वर्ल्ड ट्रेड पार्क, महालक्ष्मी नगर, जेएलएन मार्ग को क्या अनुमति दी गयी कि वह मुख्य सड़क से जुड़े मार्ग को क्रॉस कर उस पर छत को कवर कर आसपास टावर खड़े कर सकता है। जेडीए में RTI के तहत सूचना माँगने पर सूचना न मिलना और जेडीए द्वारा प्रतिउत्तर में भवन मालिकों की असहमति दर्शाना इस मामले को और संदिग्ध बनाता है!

भवन संख्या 769 सिरह ड्योद्वी बाजार, ओझा जी की हवेली चन्द्रभान ओझा को सम्बन्धित कर नगर निगम ने 21 सितंबर 2011 को नोटिस डिस्पेंस रजिस्टर में संख्या 10 में दर्ज कर एक नोटिस जारी किया जिसमें लिखा गया कि उपरोक्त पते पर

हवेली पूर्व पश्चिम मुखी का संपूर्ण भाग काफी पुराना होने के नजर से चूना पत्थर दरारे जगह-जगह से निकल रहे हैं जो कि निरास्र हालत में है जिससे आस पड़ोस वालों एवं आने जाने वाले को जान माल को खतरा हो सकता है। अतः यह नोटिस आपको नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 243 के अंतर्गत दिया जाता है व अनुरोध किया जाता है कि इसकी पालना सूचना मिलने के 2 दिन में की जाए।

लेकिन भवन मालिकों द्वारा कोई भी मरम्मत कार्य इस नोटिस के पश्चात नहीं किया गया। इसके पश्चात 12 नवंबर 2013 को भवन मालिक चन्द्रनाथ ओझा व शांतिनाथ ओझा पुत्र विद्यानाथ ओझा ने जयपुर नगर निगम में पत्रावली संख्या 27/2061 सण के तहत मलबा, छाजण, गेट, डब्ल्यू सी, झरोखा, छज्जा की अमानती राशि पच्चीस हजार चार सौ पंद्रह



रुपये रसीद संख्या 9002/571 व छः लाख इकहतर हजार तीन सौ पाँच मरम्मत लागत अनुसार एक प्रतिशत राशि रसीद संख्या 9002/573 व चाट्टर हार्वेस्टिंग राशि एक लाख रुपये रसीद संख्या 9002/572 पर जमा करवाये। इस पर नगर निगम की एम्पावर्ड कमेटी के निर्णय 18 सितंबर 2013 के तहत 25.2.2014 को केवल आवासीय प्रयोजनार्थ ओझा जी की हवेली को आवश्यक नियम निर्देश का हवाला देते हुए निर्माण स्वीकृति प्रदान की गई लेकिन 2014 से 2021 तक 7 वर्ष तक कोई भी मरम्मत या निर्माण कार्य उक्त हवेली में हवेली मालिकों द्वारा नहीं करवाया गया। 2021 में किशनपोल जोन उपायुक्त द्वारा नोटिस क्रमांक एफ52/डीसी/केपीजेड/2021/308 22.03.21 के तहत हवेली मालिकों को पुनः नोटिस जारी किया गया। जिसमें निर्माण हेतु स्वीकृति न लेने व अवैध

निर्माण करने का हवाला देते हुए पुनः निर्माण स्वीकृति लेने का आदेश दिया गया। इस पर शरद इंदुनाथ झा पुत्र चन्द्रनाथ झा ने उपायुक्त किशनपोल जोन नगर निगम हेरिटेज को 22.03.2021 को स्पष्टीकरण पत्र लिखा जिसमें उन्होंने वर्तमान निर्माण को नियमानुसार होना बताया और इसके साथ 7 वर्ष पुराने स्वीकृति पत्र संलग्न किये। संलग्न स्वीकृति पत्र की समयावधि एक वर्ष बाद यानी 25.02.2015 में ही नियमानुसार खत्म हो गयी थी लेकिन ओझा जी की हवेली मालिकों ने नगर निगम द्वारा दिए गए स्वीकृति सम्बंधित सरकारी दस्तावेजों में ओवर राइटिंग कर, काट-छाँट कर दस्तावेज नगर निगम जयपुर में प्रस्तुत कर दिए। निर्माण कार्य उक्त हवेली में हवेली मालिकों द्वारा नहीं करवाया गया। 2021 में किशनपोल जोन उपायुक्त द्वारा नोटिस क्रमांक एफ52/डीसी/केपीजेड/2021/308 22.03.21 के तहत हवेली मालिकों को पुनः नोटिस जारी किया गया। जिसमें निर्माण हेतु स्वीकृति न लेने व अवैध

निर्माण को समाप्त कर, काट-छाँट कर गुमराह करना 420 के अपराध में आता है।